आश्विन कृष्ण पक्ष-2, 2083 | dopaharmetro | epaper.dopaharmetro.com | dopaharmetro | वर्ष-10, अंक - 82 | पेज 8, मूल्य 2 रुपए

डाक पंजीयन क्रमांक: म.प्र./4-474/2024-26

बेबाक खबर हर दोपहर

दोपहर मेट्रो

भोपाल
28 सितंबर 2026
सोमवार

आज का मौसम
32.0 अधिकतम
21.0 न्यूनतम

Page-7

निर्वाचन आयोग विवाद में ज्ञानेश गुप्ता, जोशी और संधू... कोई किसी से कम नहीं

देश में चुनाव कराने वाला निर्वाचन आयोग इन दिनों खुद एक चुनावी बहस का केंद्र बन गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मुकाबला राजनीतिक दलों के बीच नहीं, बल्कि आयोग के भीतर दिखाई दे रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता एक तरफ हैं और उनके दो सहयोगी निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा डॉ. विवेक जोशी दूसरी तरफ दिखाई दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि तीनों कोई मामूली अफसर नहीं हैं, लंबी प्रशासनिक पृष्ठभूमि से आए हैं और व्यवस्था को भीतर से समझते हैं। इसलिए सवाल केवल यह नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, सवाल यह है कि आखिर आयोग के भीतर ऐसा क्या हुआ कि दो आयुक्तों को बार-बार लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज करनी पड़ी?

प्रसंगवश

राजेश सिरोठिया

ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच के अधिकारी रहे हैं। वे केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। ऊर्जा, सहकारिता तथा संसदीय कार्य से जुड़े मंत्रालयों में वरिष्ठ पदों पर काम कर चुके हैं। निर्वाचन आयोग में आने से पहले वे केंद्रीय गृह मंत्रालय में सचिव रहे। उन्हें 2024 में निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया और फरवरी 2025 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का दायित्व मिला। उनका कार्यकाल जनवरी 2027 तक है। सुखबीर सिंह संधू भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच के अधिकारी हैं। वे उत्तराखंड कैडर से आते हैं और उत्तराखंड के मुख्य सचिव तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। उन्हें जुलाई 2022 में निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल सितंबर 2027 तक है। यानी वे आयोग में ज्ञानेश कुमार से पहले आए और प्रशासनिक अनुभव के लिहाज से भी किसी से कम नहीं हैं। डॉ. विवेक जोशी1989 बैच के हैं। वे हरियाणा कैडर से आते हैं और केंद्र सरकार में वित्त सचिव तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव जैसे पदों पर काम कर चुके हैं। उन्हें फरवरी 2025 में निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल मई 2029 तक है। इस तरह आयोग में तीनों की नियुक्ति और कार्यकाल की अवधि अलग-अलग है, लेकिन तीनों का प्रशासनिक अनुभव लंबा और उच्च स्तर का है।

हाल में सामने आई इंडियन एक्सप्रेस की विस्तृत रिपोर्ट के मुताबिक संधू और विवेक जोशी ने पिछले दस महीनों में आयोग के कुछ निर्णयों और प्रक्रियाओं पर कम-से-कम 14 बार औपचारिक आपत्ति दर्ज की। ये आपत्तियां मतदाता सूची के पुनरीक्षण, नए मतदाताओं के पंजीयन, नाम हटाने और बहाल करने की प्रक्रिया तथा मतदाता सूची से जुड़े आईटी सिस्टम के नियंत्रण जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दों पर थीं।

अब जरा Form-6 का मामला देखिए। नए मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने के लिए इस्तेमाल होने वाले इस फॉर्म में एसआईआर यानी विशेष सघन मतदाता सूची में पुनरीक्षण से संबंधित एक नया सवाल जोड़े जाने पर विवेक जोशी ने मई में आपत्ति दर्ज की थी। उनका तर्क था कि यह वैधानिक फॉर्म है और इसे मतदाता पंजीयन नियम 1960 में संशोधन किए बिना बदला नहीं जा सकता। संधू ने भी इस आपत्ति से सहमति जताई। बाद में संधू ने इसे अनाधिकृत और अवैध बताते हुए तत्काल हटाने की मांग की। यहीं से मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। क्योंकि निर्वाचन आयोग कोई मंत्रालय नहीं है, जहां फाइल पर असहमति दर्ज कर अधिकारी आगे बढ़ जाए और मामला समाप्त हो जाए। यह वह संस्था है जिसके एक फैसले से किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची में जुड़ सकता है और दूसरे फैसले से हट सकता है। लिहाजा यहां प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अंतिम निर्णय। दूसरा मुद्दा मतदाता सूची के डिजिटल नियंत्रण का है। रिपोर्टों के अनुसार दोनों निर्वाचन आयुक्तों ने इस बात पर भी सवाल उठाए कि कहीं मतदाता सूची से संबंधित अधिकार धीरे-धीरे केंद्रीय स्तर पर तो नहीं सिमट रहे। परंपरागत व्यवस्था में मतदाता पंजीयन अधिकारी यानी ईआरओ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यदि डिजिटल सिस्टम ही उसके निर्णय को लागू करने में बाधा बने तो सवाल स्वाभाविक है कि अंतिम नियंत्रण किसके हाथ में है?

निर्वाचन आयोग ने मीडिया रिपोर्ट और बहस के बीच स्पष्ट किया कि आयोग में विचार-विमर्श और अलग-अलग मत होना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है तथा अंतिम निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। 26 सितंबर की बैठक के बाद आयोग ने एसआईआर और मतदाता पंजीयन से जुड़े कई मुद्दों पर नए निर्णय और स्पष्टीकरण भी जारी किए। तो फिर असली सवाल क्या है? सवाल यह नहीं कि ज्ञानेश कुमार बड़े हैं या विवेक जोशी और संधू छोटे। तीनों अपने-अपने अनुभव और संवैधानिक दायित्व के साथ आयोग में बैठे हैं। तीनों अलग-अलग समय पर नियुक्त हुए हैं और तीनों के कार्यकाल की अवधि भी अलग है। लेकिन नियुक्ति की तारीख या पदक्रम से किसी की प्रशासनिक समझ छोटी-बड़ी नहीं हो जाती। सवाल यह है कि अगर दो निर्वाचन आयुक्त किसी प्रक्रिया पर बार-बार लिखित आपत्ति करते हैं, तो उन आपत्तियों का संस्थागत समाधान कैसे होता है? क्या उन्हें सार्वजनिक करने की जरूरत है? क्या आयोग के भीतर मतभेदों को दर्ज करने की कोई पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण यह कि क्या देश को यह जानने का अधिकार है कि मतदाता सूची जैसे संवेदनशील विषय पर निर्णय किस प्रक्रिया से लिए गए ?

कैबिनेट सेक्रेटरी को पत्र के पीछे कौन सी रणनीति ?

एक बड़ा सवाल यह है भी है कि दोनों मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को ज्ञानेश गुप्ता से कुछ मसलों पर आपत्ति थी तो उन्होंने केबिनेट सेक्रेटरी की ओर रूख क्यों किया? सुख़बीर सिंह संधू उत्तराखंड और विवेक जोशी हरियाणा के मुख्य सचिव के बतौर काम कर चुके हैं । क्या उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कैबिनेट सेक्रेटरी की बजाय महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष आपत्ति दर्ज कराना थी क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं और वे चुनाव आयुक्त के रूप में केबिनेट सेक्रेटरी के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। क्या वे इतने अनजान हैं? या फिर बात कुछ और ही है? खबरें यह भी उछाली जा रही हैं कि किसी सोची समझी रणनीति के तहत कैबिनेट सेक्रेटरी को पत्र लिखा या लिखवाया गया। मामला चूंकि पब्लिक डोमेन में है तो दोनों का सामने आकर अपनी बात खुलकर रखनी चाहिए।

लोकतंत्र में असहमति, सावधानी की पहली सीढ़ी

लोकतंत्र में असहमति कोई बीमारी नहीं है। बल्कि गंभीर संस्थाओं में असहमति कई बार सावधानी की पहली सीढ़ी होती है। लेकिन असहमति का समाधान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर दो आयुक्त लिख रहे हों और तीसरा अपनी प्रक्रिया पर कायम हो, तो आखिर में देश को केवल सर्वसम्मति का बयान नहीं, उस सर्वसम्मति तक पहुंचने की प्रक्रिया पर भी भरोसा चाहिए। क्योंकि चुनाव केवल वोट डालने का दिन नहीं है। चुनाव उससे बहुत पहले शुरू हो जाता है, मतदाता सूची से। और यही कारण है कि ज्ञानेश कुमार, विवेक जोशी और संधू साब के बीच चल रही यह बहस किसी तीन अफसरों की आपसी तकरार भर नहीं मानी जा सकती। यह उस संस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा सवाल है, जिसके हाथ में देश के लोकतांत्रिक जनादेश की पूरी प्रक्रिया है। तीनों में कौन किससे कम है, यह तय करना मेरा या किसी राजनीतिक दल का काम नहीं। लेकिन तीनों से एक जैसी अपेक्षा जरूर है- निर्वाचन आयोग के फैसले पर देश को भरोसा हो और उस भरोसे के पीछे प्रक्रिया भी उतनी ही साफ दिखाई दे। आखिर लोकतंत्र में मतदाता सिर्फ अपना वोट नहीं देता, वह अपना भरोसा भी देता है। और भरोसा जितना बड़ा होता है, उसकी पारदर्शिता की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है।

न्यूज विंडो

असम में 2 करोड़ की हेरोइन जब्त, एक गिरफ्तार

गुवाहाटी। असम के गुवाहाटी में पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 262 ग्राम संदिग्ध हेरोइन बरामद की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के मुताबिक, जब्त ड्रग्स की अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा कि असम पुलिस ने ड्रग्स की तस्करी की कोशिश को नाकाम किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुवाहाटी के सिउज नगर इलाके में की।

बृजभूषण को बरी करने के खिलाफ कोर्ट पहुंचीं 4 महिला पहलवान

नई दिल्ली। भाजपा नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न के मामले में बरी किए जाने के खिलाफ चार महिला पहलवानों ने सत्र अदालत का रुख किया है। पहलवानों ने सह-आरोपित रहे विनोद तोमर के बरी होने को भी चुनौती दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने आज अपील पर नोटिस जारी किया और मामले को नौ अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

लगातार 8वें हफ्ते बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 1000 अंक गिरा

मुंबई। बीते शुक्रवार 25 सितंबर को लगातार सातवें हफ्ते लाल निशान में बंद होने के बाद, आज भी बाजार में गिरावट है। सेंसेक्स 1000 अंक या 1.30% की गिरावट के साथ 72,900 से नीचे कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 300 अंक या 1.30% की गिरावट है, ये 22,850 पर कारोबार कर रहा है। बैंकिंग, FMCG शेयर्स में आज ज्यादा बिकवाली है।

चुनाव आयोग में तलवारबाजी कांग्रेस की ही देन, अब इसी पर खड़ा कर रही सियासी सवाल
वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री आलोक मेहता का विशेष लेख... पेज – 4

आज का कार्टून

उज्जैन में मस्जिद का हिस्सा हटाने को लेकर भारी बवाल

सिंहस्थ के लिए सड़क को 15 मीटर चौड़ा किया जा रहा है पुलिस एक्शन के बाद मुस्लिम समाज मस्जिद तोड़ने को राजी

पुलिस पर पथराव, आंसू गैस के गोले दागने पड़े, महिला इंस्पेक्टर घायल

उज्जैन, दोपहर मेट्रो

यहां शाही मस्जिद का कुछ हिस्सा हटाने को लेकर आज बवाल हो गया। कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया जिन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इस बीच महिलाओं ने चक्काजाम कर दिया। हंगामे और पुलिस कार्रवाई के बाद मुस्लिम समाज खुद आगे आया और मस्जिद का हिस्सा खुद ही तोडना शुरू कर दिया है। खबर है कि प्रदर्शन का रहीं महिलाओं को हटाने के दौरान शहर की क्राइम ब्रांच थाना प्रभारी पुष्पा पांचाल घायल हो गईं। मस्जिद हटाने के मामले पर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में आज ही सुनवाई निर्धारित है। उल्लेखनीय है कि सिंहस्थ के लिए कंठाल चौराहे से गोपाल मंदिर तक की 900 मीटर की सड़क को 15 मीटर चौड़ा किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि शाही मस्जिद का हिस्सा हटाने के फैसले का विरोध स्थानीय मुस्लिम समाज लगातार दो दिनों से कर रहा है। रविवार रात जब जेसीबी और पोकलेन मशीनों के साथ भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा तो बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और देर रात तक विरोध जारी रहा था। आज सुबह से फिर भीड़ जमा हो गई और पथराव करने लगी। कुछ वीडियो सामने आए हैं जिनमें युवक पथराव करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने उपद्रव रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े । कुछ देर तक पथराव के बाद पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया और भीड़ को तितर-बितर किया गया। कुछ देर बाद दोबारा पथराव शुरू हो गया।

इस दौरान क्राइम ब्रांच में पदस्थ टीआई पुष्पा पांचाल के हाथ में चोट लग गई। पुलिस के अनुसार, कुछ महिलाएं विरोध के दौरान आगे बढ़ रही थीं। महिला पुलिस बल को सुरक्षा देने और महिलाओं को सुरक्षित तरीके से हटाने के दौरान पुलिसकर्मी चादर की आड़ में मौजूद महिलाओं के बीच पहुंचे। इसी दौरान टीआई पुष्पा पांचाल के हाथ में चादर के कोने से कट लग गया। मौके पर अब भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने विरोध के दौरान मस्जिद परिसर में जाने की कोशिश की है, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया है। इस बीच बड़ी संख्या में महिलाएं सड़क बैठ गई हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उज्जैन शहर में करीब 2000 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। जिसमें आरएएफ और एसटीएफ के जवान भी शामिल हैं। शहर के काजी खलीकुर्रहमान के साथ प्रशासन ने बातचीत की है।

100 साल से ज्यादा पुरानी मस्जिद

मस्जिद प्रबंधन का दावा है कि उज्जैन की शाही मस्जिद 100 साल से ज्यादा पुरानी है। कुछ रिपोर्ट्स में प्रदर्शनकारियों के हवाले से इसे 600 साल पुरानी बताया गया है। मस्जिद प्रबंधन के मुताबिक, 17 मार्च 1925 के सिंधिया राजघराने के समय के दस्तावेज में जमीन अधिग्रहण के बाद मस्जिद के बचे हिस्से को जस का तस रखने का उल्लेख है। इसके बाद 1975 में सड़क और यातायात के लिए मस्जिद प्रबंधन ने अपनी कुछ जमीन देने का दावा किया है। 13 सितंबर 1985 के मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र में भी मस्जिद और उसकी नपाई का जिक्र होने की बात सामने आई है।

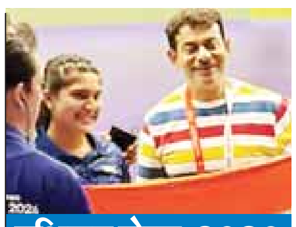

एशियन गेम्स-2026

ईशा सिंह ने भारत को सिल्वर दिलाया

टोक्यो। शूटर ईशा सिंह ने भारत को एशियन गेम्स 2026 के 9वें दिन का पहला मेडल दिलाया। वे आज विमेंस 25 मीटर पिस्टल इवेंट के फाइनल में दूसरे स्थान पर रही। चीन की खिलाड़ी ने शूटऑफ जीतकर गोल्ड मेडल जीता। ईशा ने 580 अंक के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। जबकि, मनु भाकर (579 अंक) बाहर हो गई हैं। वहीं, टीम इंडिया 1727 अंक के साथ 5वें स्थान पर रही। फिलहाल, भारत मेडल टैली के 12वें स्थान पर है। उसके पास 38 मेडल हैं। इनमें 4 गोल्ड, 16 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज शामिल हैं।

बारिश के कारण मैच रद्द

बिना टॉस हुए सेमीफाइनल में पहुंचे भारत और पाक

निशिन। भारत और अफगानिस्तान के बीच एशियन गेम्स में क्रिकेट का क्वार्टर फाइनल बारिश की वजह से बिना टॉस हुए रद्द हो गया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। इससे पहले भी इस वेन्यू पर पाकिस्तान और हॉन्गकॉन्ग के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला बिना टॉस के रद्द हुआ था।

बिहार में बाढ़ से 82 हजार प्रभावित

उत्तराखंड में बर्फबारी से 136 पर्वतारोही फंसे, यूपी में पुल डूबे

नई दिल्ली। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से आदि कैलाश मार्ग समेत 86 सड़कें बंद हैं। इनमें चमोली की 21, नैनीताल की 18 और पिथौरागढ़ की 15 सड़कें शामिल हैं। बर्फबारी के बीच उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में 136 पर्वतारोही, ट्रैकर और सपोर्ट स्टाफ फंसे हैं। उनका रेस्क्यू किया जा रहा है।

वहीं, नेपाल से गंडक नदी में पानी छोड़े जाने के बाद बिहार के पश्चिम चंपारण और सुपौल के 23 गांवों में बाढ़ आ गई। बाढ़ से करीब 82 हजार लोग प्रभावित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 4 दिनों से लगातार बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। गोंडा और बदायूं में छोटे पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। आंधी-बारिश से पिछले 2 दिनों में 63 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कुशीनगर में 2 गांवों के 1,400 परिवार प्रभावित हैं। राज्य के 46 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

पंजाब के एलपीयू में विवाद

छात्रों के हिंसक विरोध के बाद क्लास सस्पेंड, इंटरनेट सेवा बंद

फगवाड़ा। पंजाब के फगवाड़ा में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में छात्रों के हिंसक विरोध के बाद एलपीयू ने आज से 10 दिनों के लिए रेगुलर क्लास सस्पेंड कर दी हैं। इसके अलावा खबर ये भी है कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और आसपास के इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है।

पंजाब सीएमओ के मुताबिक, 'लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने डीजीपी गौरव यादव को घटनास्थल पर जाकर स्थिति का जायजा लेने का निर्देश दिया है।' लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) में छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर 27वीं बटालियन की कमांडेंट गुरमीत कौर ने कहा, 'हमने पांच युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक दरांती (हंसिया जैसा हथियार) और एक वॉकी-टॉकी बरामद की गई है।

गैंगरेप पर भड़का सुप्रीम कोर्ट

गंभीर लापरवाही: यह पुलिस और प्रशासन की नाकामी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में हाल ही में सामने आए दुष्कर्म के मामलों पर गहरी चिंता और नाराजगी जताई है। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ये घटनाएं कानून प्रवर्तन एजेंसियों और प्रशासनिक अधिकारियों की सिस्टमैटिक नाकामी को साफ तौर पर उजागर करती हैं, जो नागरिकों को बुनियादी सार्वजनिक सुरक्षा तक मुहैया कराने में असफल साबित हो रहे हैं।

शीर्ष अदालत के अनुसार, महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार करने में व्यवस्था की यह लापरवाही बेहद गंभीर है और यह दर्शाता है कि जमीनी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था और जवाबदेही दोनों पूरी तरह चरमरा चुकी हैं। शीर्ष अदालत ने इन घटनाओं पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि इनमें 2012 के निर्भया कांड जैसी दर्दनाक समानताएं दिखाई देती हैं। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इन मामलों की सुनवाई करते हुए कहा कि ये घटनाएं कानून लागू करने वाली एजेंसियों की स्पष्ट विफलता को दर्शाती हैं।

न्यूज विंडो

उर्दू विवि की छात्रा को बेकाबू कार ने रौंदा, चालक फरार

भोपाल। गांधीनगर के हाईटेक सिटी इलाके में शनिवार रात सड़क पार कर रही छात्रा को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। गंभीर घायल छात्रा को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया। यहां इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका सेम शाहिद (22) पिता फैजान अहमद मूलतः बिहार के वैशाली की रहने वाली थी। वह भोपाल में हाईटेक सिटी में किराए से रहकर मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। सेम सहेलियों के साथ ढाबे से खाना लेकर पैदल लौट रही थी। तभी गांधी नगर से आई काले रंग की कार ने टक्कर मार दी। हादसे में उसिर, गर्दन, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आईं। सेम की सहेली बुशरा ने कार का नंबर नोट किया था। पुलिस कार की तलाश कर रही है।

ब्रेड में फफूंद...खाद्य विभाग की टीम पहुंची ब्लिंकिट स्टोर, की जांच

भोपाल। खाद्य की टीम ने रविवार को सलैया स्थिति ब्लिंकिट की जांच की। यहां से एक उपभोक्ता को फफूंद लगी ब्रेड आपूर्ति का मामला हुआ था। टीम को प्रतिष्ठान में खाद्य लाइसेंस चस्पा हुआ नहीं मिला। प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र से कर्मचारियों के

मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र भी नहीं थे। कर्मचारियों ने एप्रन, ग्लव्स, कैप का उपयोग नहीं किया था। प्रतिष्ठान से टॉप एंड टाउन मल्टीग्रेन ब्रेड का नमूना लिया। प्रयोगशाला से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। टीम ने गौतम नगर स्थित फूड अड्डा रेस्टोरेंट की जांच की। वेज बिरयानी का नमूना लिया। टीम ने कुरावर में मिल्क पाउडर कंपनी की भी जांच की।

आईएसबीटी पर रहे व्यापारी का मोबाइल ले भागे बदमाश

भोपाल। गोविंदपुरा थाना क्षेत्र स्थित आईएसबीटी बस स्टैंड के पास पत्नी के साथ बस का इंतजार कर रहे हार्डवेयर व्यापारी का आईफोन बाइक सवार दो अज्ञात बदमाश झपटकर ले गए। फरियादी ने ससुराल लौटने पर थाने जाकर प्रकरण दर्ज कराया है। झपटे गए

आईफोन की कीमत 90 हजार रुपए बताई जा रही है। विराट कॉलोनी सतना निवासी रोशन विश्वकर्मा (26) की सतना में ही हार्डवेयर की दुकान है। उनकी ससुराल यहां नारायण नगर में है। वह अपनी पत्नी को लेने नारायण नगर आए थे।

3000 से ज्यादा सीटों पर आयुष मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश आज से

भोपाल। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग व राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आयुष कॉलेजों में 28 से 29 सितंबर तक स्नातक स्तर पर दो दिन होंगे। इसके लिये पं खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद कॉलेज में रिपोटिंग कर अभिलेख सत्यापन उपरांत

औपचारिकता पूर्ण कर अलॉटेड कॉलेज में प्रवेश होंगे। स्टेट कोटे की 85 प्रतिशत सीटों में प्रवेश हेतु रिवाइज्ड मेरिट सूची के पश्चात सीट आवंटन 28 सितंबर यानी आज होगा। अलॉटेड कॉलेज में स्नातक में प्रवेश 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होंगे। आयुष मेडिकल एसो. राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ राकेश पाण्डेय ने बताया कि एमपी ऑनलाइन के माध्यम से जारी सूची के अनुसार प्रथम चरण की काउंसलिंग में भोपाल समेत प्रदेश के 41 आयुष मेडिकल कॉलेजों की तीन हजार से ज्यादा सीटों पर छात्र काउंसलिंग से प्रवेश लेंगे।

कानफोडू शोर..रास्ते रोके, ट्रैफिक बाधित... 10 डीजे पर कार्रवाई,

भोपाल। गणेश प्रतिमा विसर्जन के चल समारोह में यातायात बाधित कर तेज आवाज में डीजे बजाने वाले 10 डीजे संचालकों पर पुलिस ने एक्शन लिया गया है। उनके खिलाफ यातायात बाधित करने और निर्धारित ध्वनि सीमा का उल्लंघन करने के आरोप में प्रकरण दर्ज किए हैं। इसमें तलैया थाने में 4, कोतवाली में 3, गौतम नगर में 2 और हनुमानगंज में 1 डीजे संचालक पर केस दर्ज किया है। इतवारा चौराहा, रात दो बजे सेंट्रल लाइब्रेरी के पास और तड़के 4 बजे मोती मस्जिद के पास डीजे लगे ट्रैक्टर पर कार्रवाई की गई। वहीं, हनुमानगंज पुलिस ने सपना लॉज के पास छोला रोड पर पवार डीजे वाहन पर केस दर्ज किया।

त्योहार के लिए स्पेशल ट्रेन..अगले माह बदले रूट से चलेंगी 23 ट्रेनें

भोपाल। दशहरा, दिवाली और छठ पूजा पर घर लौटने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। अक्टूबर में एक साथ भोपाल से गुजरने वाली 23 ट्रेनों के बदले हुए रूट से चलेंगी।

इन ट्रेनों का बदलेगा मार्ग

छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-गोरखपुर: 14 अक्टूबर को कल्याण-करजत-पुणे-मनमाड़ होकर चलेगी।
अगरतला-लोकमान्य तिलक टर्मिनस: 15 अक्टूबर को मनमाड-पुणे-लोणावला-कल्याण होकर चलेगी।
गोमतीनगर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पुष्पक: 16 अक्टूबर को जलगांव-नंदुरबार-बसई रोड-ठाणे होकर चलेगी।
गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस: 16 अक्टूबर को जलगांव-नंदुरबार-बसई रोड-ठाणे होकर चलेगी।
एर्नाकुलम-लोकमान्य तिलक टर्मिनस: 16 अक्टूबर को बसई रोड-नंदुरबार-जलगांव होकर चलेगी।
अमृतसर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस: 16 को मनमाड-पुणे-लोणावला-कल्याण के रास्ते।
भागलपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस: 16 अक्टूबर को मनमाड-पुणे-लोणावला-कल्याण होकर चलेगी।
प्रयागराज-लोकमान्य तिलक टर्मिनस: 16 अक्टूबर को ठाणे-बसई रोड-नंदुरबार-जलगांव होकर चलेगी।

बप्पा तो अपने गांव लौट गए, पर निगम की अनदेखी से तालाब में स्वच्छता गायब

भोपाल। राजधानी में गणेशोत्सव के भव्य समापन और प्रतिमा विसर्जन के दो दिन बाद भी प्रमुख घाटों पर लापरवाही देखी जा रही है। छोटा तालाब के खटलापुरा घाट और रानी कमलापति घाट पर प्रतिमा विसर्जन के बाद उपयोग किए गए लकड़ी के काफी अवशेष अब भी पड़े हुए हैं। हालांकि नगर निगम ने सफाई का काम शुरू कर दिया है। लेकिन इसकी रफ्तार बेहद धीमी है।

भोपाल मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में तकनीक का प्रस्ताव, करेंगे कैसे...साफ नहीं

'डिजिटल ट्विन' से स्मार्ट बनेगा शहर, पर सही डेटा मिलेगा कैसे

सबसे पहले पूरे शहर का एक डिजिटल डेटा बनाना होगा | **सड़क-पानी, बिजली-ट्रैफिक की जानकारी लाइव दिखेगी** | **एक्सपर्ट कह रहे-नियम ही जब साफ नहीं तो होगा कैसे**

भोपाल। दोपहर मेट्रो

राजधानी भोपाल को अगले 23 सालों के हिसाब से संवारने के लिए 'भोपाल मास्टर प्लान 2047' का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इस प्लान में शहर की तरक्की के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं। इनमें सबसे खास है भोपाल को 'डिजिटल ट्विन सिटी' बनाना। यानी असली भोपाल की तर्ज पर कंप्यूटर स्क्रीन पर एक 'डिजिटल भोपाल' तैयार किया जाएगा, जिससे शहर की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। लेकिन योजना जितनी अच्छी कागजों पर दिख रही है, जमीन पर उतारना उतना ही चुनौतीपूर्ण है। शहरी नियोजन विशेषज्ञों का मानना है कि इस हाइटेक व्यवस्था को लागू करने से पहले भोपाल में मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सटीक डेटा सिस्टम खड़ा करना होगा। ड्राफ्ट को देखें तो इस हिसाब से भविष्य की योजना बहुत अच्छी है, लेकिन प्लान के ड्राफ्ट में इसे पूरा करने का तरीका नहीं बताया गया है। इसके लिए बजट की व्यवस्था कहां से होगी, यह भी साफ नहीं है। सबसे खास है ड्राफ्ट में पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए। तभी यह जमीन पर उतर सकेगा। इस पर अभी बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति है।

'डिजिटल ट्विन'..कैसे काम करेगा?

डिजिटल ट्विन का मतलब है शहर की हर एक इमारत, सड़क, बिजली लाइन, पानी की पाइपलाइन, सीवरेज, बस सेवा और पार्कों का एक लाइव थ्री-डी मॉडल। अगर शहर में कहीं पानी की पाइपलाइन फूटती है या किसी चौराहे पर भारी ट्रैफिक जाम लगता है, तो डिजिटल मॉडल में अफसरों को तुरंत इसका पता चल जाएगा। वे बिना मौके पर पहुंचे कम्प्यूटर स्क्रीन से ही स्थिति को समझकर सही कदम उठा सकेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके लिए पहले जमीनी तैयारी करनी जरूरी है। भोपाल स्थित 'स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर' (एसपीए) के प्रोफेसर मयंक दुबे का कहना है कि योजना सफल हो सकती है। लेकिन इसमें कुछ सुधार करने होंगे। रीयल टाइम डेटा की जरूरत होगी। डिजिटल ट्विन के लिए सबसे खास यह है कि लोगों का हर छोटे-मोटे काम के लिए सरकारी दफ्तरों की दौड़ बंद करानी होगी। यह सब तब होगा, जब लोगों को डिजिटल सेवा बेहतर मिलेगी।

एक्सपर्ट के ये सुझाव

वास्तविक समय का डेटा: डिजिटल शहर तभी काम करेगा जब बस सेवा, पानी की सप्लाई और बिजली विभाग का डेटा तुरंत और लगातार अपडेट होता रहे। अगर डेटा पुराना होगा, तो डिजिटल मॉडल बेकार साबित होगा।
दफ्तरों के चक्कर बंद हों: मास्टर प्लान में लक्ष्य तो तय कर दिए गए हैं, लेकिन यह साफ नहीं है कि कौन सा विभाग क्या काम करेगा। जब तक जिम्मेदारियां और समयसीमा तय नहीं होगी, आम जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने ही पड़ेंगे।
ऊंची इमारतें बनाने से विकास नहीं: मास्टर प्लान में चौड़ी सड़कों के किनारे बहुत ऊंची इमारतें (वर्टिकल ग्रोथ) बनाने की छूट दी गई है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि भोपाल में जमीन अभी सस्ती है, इसलिए सिर्फ नियम बदलने से लोग अचानक बहुमंजिला इमारतें नहीं बनाने लगेंगे।
ट्रैफिक और पार्किंग की नई व्यवस्था: शहर में 91 किमी का नया ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनना है, जिसमें सालों लगेंगे। तब तक आज के ट्रैफिक जाम से निपटने का क्या प्लान है? केवल बड़ी पार्किंग बना देने से जगह नहीं मिलेगी, बल्कि सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियों का बेहतर मैनेजमेंट करना होगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन

पहले सभा में बरसे, फिर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का दफ्तर घेरने निकले कांग्रेसी

भोपाल। दोपहर मेट्रो

प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर कांग्रेस आज भोपाल में बड़ा प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से अरेरा हिल्स स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय का घेराव करने निकले हैं। विधायक, पूर्व विधायक, प्रदेश पदाधिकारी सहित भोपाल और प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हजारों कार्यकर्ता शामिल हैं। आंदोलन की पृष्ठभूमि में द इंडियन एक्सप्रेस की वह रिपोर्ट है, जिसमें चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से 10 माह में वोटर लिस्ट, एसआईआर से जुड़े कुछ फैसलों पर 14 आपत्तियां दर्ज कराने की बात सामने आई थी। चुनाव आयोग ने बाद में कहा कि आयोग के फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे। कांग्रेस केवल आंकड़ों तक सीमित न रहकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग कर रही है।

घेराव से पहले सभा, जीतू बोले-मप्र में 34.25 लाख वोटरों के नाम हटाए

घेराव आंदोलन से पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने विशाल सभा की। इस दौरान मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, पूर्व सांसद रामेश्वर

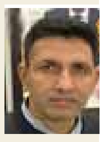

नीखरा, पीसी शर्मा, पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो, मुकेश नायक, रवि जोशी, संजय कामले, विधायक सिद्धार्थ कुशवाह, शोभा ओझा, विक्की पटेल सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। पटवारी ने कहा, एसआईआर में मप्र की अंतिम मतदाता सूची से 34. 78 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए। पहले 5,74,06,143 वोटर थे। 42,74,160 नाम बाहर कर दिए। 21 फरवरी को जारी अंतिम सूची में 5.39 लाख वोटर ही बचे। हटाए गए नामों का विधानसभा व जिलावार ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की।

पुलिस ने लिए शिकायतकर्ता के बयान, लेन-देन की कर रही जांच

फर्जी IAS तृप्ति केस में शिकायत करने वाला भी आरोपी, युवती को नौकरी दिलाने का झांसा देने किया था फोन

भोपाल। दोपहर मेट्रो

फर्जी आईएएस बनकर ठगी करने के आरोपों से घिरी तृप्ति सिंह के मामले में नया मोड़ आ गया। बागसेवनिया पुलिस ने जांच के दौरान शिकायतकर्ता रहे रोहित लिल्हारे को भी आरोपी बना दिया। पुलिस के मुताबिक तृप्ति के कहने पर रोहित ने एक युवती से फोन पर बात कर उसे नौकरी का जॉइनिंग लेकर और पुलिस वेरिफिकेशन कराने के संबंध में बात की थी। और सिर्फ मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) से सत्यापन बाकी होने की बात कही गई थी। कॉल डिटेल की जांच के बाद पुलिस ने उसकी भूमिका संदिग्ध मानते हुए कार्रवाई की है। अब तक पांच आरोपी हो गए हैं।

रोहित लिल्हारे के बयान दर्ज किए गए। पुलिस उसके तृप्ति से संपर्क, युवती से हुई बातचीत और बैंक खातों में लेन-देन की जांच कर रही है। तृप्ति ने युवतियों के साथ विधानसभा के अंदर बनाए गए वीडियो रोहित को भेजे थे और नौकरी लगने की बात कही थी।

पुलिस के अनुसार झांसे में रोहित ने तृप्ति को 40 लाख रुपए दिए थे। हालांकि लेन-देन और उसकी भूमिका की जांच जारी है। रोहित ने ही तृप्ति के खिलाफ पहला मामला दर्ज कराया था। इसमें तृप्ति के भाई सुधांशु सिंह, प्रखर सिंह और ड्राइवर भूपेंद्र बैरागी भी आरोपी थे और सितंबर के पहले सप्ताह में गिरफ्तार हुए थे। तृप्ति और अन्य आरोपियों पर अशोकनगर कोतवाली में भी मामला दर्ज है।

मोबाइल नंबर की जांच

ख्याति ने तृप्ति पर खुद को पर्यटन विभाग की अतिरिक्त संचालक बताकर नौकरी के नाम पर डेढ़ लाख रुपए लेने का आरोप लगाया था। इस मामले में दर्ज मोबाइल नंबर के आधार पर अब रोहित को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस सीडीआर और बैंक रिकॉर्ड के जरिए मामलों की कड़ियां जोड़ रही है।

भोपाल रेलवे स्टेशन के कर्मचारी पर यात्री का आरोप

टिकट लेने पहुंचे यात्री से बदसलूकी वीडियो डिलीट कराने दी धमकी

भोपाल। भोपाल रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने पहुंचे यात्री सुनील ने महिला कमर्शियल क्लर्क मीना पर कथित तौर पर यात्रियों से अभद्र व्यवहार करने और ड्यूटी के दौरान ईयरबड लगाए रखने का आरोप लगाया है। सुनील के अनुसार, टिकट लेने के दौरान भी संबंधित कर्मचारी के कानों में ईयरबड लगे हुए थे, जिससे बातचीत और टिकट संबंधी जानकारी लेने में परेशानी हुई।

सुनील ने बताया कि उन्होंने इसका वीडियो बना लिया। आरोप है कि वीडियो बनाए जाने के बाद रेलवे के एक कर्मचारी और आरपीएफ के एक जवान ने उनसे वीडियो डिलीट करने के लिए दबाव बनाया। सुनील का कहना है कि वीडियो डिलीट नहीं करने पर प्राथमिकी दर्ज कराने की धमकी भी दी गई। सुनील के मुताबिक, पूरे घटनाक्रम का रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड होना बताया जा रहा है। उन्होंने रेलवे अधिकारियों से सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित कर मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। आरपीएफ अधिकारियों का कहना है कि मामले में कोई शिकायत हमें नहीं मिली है। हां, ऐसी सूचना मिली थी। जांच की जाएगी।

मेट्रो एंकर 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र, अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना, 19 को दिन में संधि पूजा का विशेष योग

10 दिन शक्ति की साधना, हाथी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा

भोपाल। दोपहर मेट्रो

शक्ति उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र इस वर्ष 11 अक्टूबर रविवार से शुरू होकर 20 अक्टूबर मंगलवार तक चलेगा। तिथि वृद्धि के कारण इस बार नवरात्र पर्व 10 दिनों का रहेगा। अष्टमी तिथि दो दिन रहने से श्रद्धालुओं को मां भगवती की आराधना के लिए अतिरिक्त अवसर मिलेगा।

नवरात्र के दौरान मंदिरों और घरों में घटस्थापना, दुर्गा सप्तशती पाठ, हवन, कन्या पूजन और विशेष अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा। ब्रह्म शक्ति ज्योतिष संस्थान के ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष पंडित जगदीश शर्मा ने बताया कि नवरात्र के प्रथम दिन घटस्थापना का विशेष धार्मिक महत्व होता है।

इस वर्ष नवरात्र के प्रथम दिन पूरे समय चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग की स्थिति रहेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसी स्थिति में सामान्य समय में कलश स्थापना को शुभ नहीं माना जाता। इसलिए अभिजीत मुहूर्त में घटस्थापना करना शास्त्र सम्मत माना गया है।

47 मिनट रहेगा घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त

11 अक्टूबर को घटस्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:20 बजे से दोपहर 12:07 बजे तक रहेगा। इस दौरान श्रद्धालु विधि-विधान से कलश स्थापना कर मां दुर्गा की पूजा शुरू कर सकेंगे। इस वर्ष मां दुर्गा का आगमन हाथी पर आएंगी। मान्यताओं में हाथी को वर्षा, समृद्धि और प्राकृतिक संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। वहीं नवरात्र का समापन मंगलवार को होने के कारण भगवती का गमन कुक्कुट (मुर्गे) पर माना गया है।

संधि काल में ही माता ने चंड-मुंड का वध किया था

नवरात्र में महाअष्टमी की समाप्ति और महानवमी के आरंभ के बीच का समय संधि काल कहलाता है। इस अवधि में होने वाली संधि पूजा का विशेष धार्मिक महत्व है। शास्त्रीय परंपरा के अनुसार अष्टमी तिथि के अंतिम 24 मिनट और नवमी तिथि के प्रारंभिक 24 मिनट को मिलाकर संधि काल माना जाता है। इस वर्ष 19 अक्टूबर सोमवार को सुबह 10:27 बजे से 11:15 बजे तक संधि पूजा का विशेष समय रहेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी संधि काल में मां दुर्गा ने चामुंडा स्वरूप धारण कर चंड और मुंड नामक असुरों का संहार किया था। इसलिए इस अवधि में देवी की विशेष पूजा, दीप प्रज्ज्वलन और आराधना का महत्व माना जाता है।

नवरात्र के समापन के बाद 20 अक्टूबर को विजयादशमी मनाई जाएगी। वहीं 21 अक्टूबर को नवरात्र व्रत का पारण किया जाएगा। नवरात्र के दौरान श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कन्या पूजन, हवन, दान-पुण्य तथा धार्मिक अनुष्ठान करेंगे। श्रद्धालुओं से नवरात्र के दौरान श्रद्धा, संयम और विधि-विधान के साथ मां भगवती की आराधना करने का आह्वान किया।

व्यापमं कंप्यूटर खरीदी घोटाला : 18 साल पुराने केस में फोटोकॉपी से होगी सुनवाई

भोपाल कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में रखी फाइलें खा गई दीमक

भोपाल, दोपहर मेट्रो

व्यावसायिक परीक्षा मंडल के 18 साल पुराने कंप्यूटर खरीदी घोटाले में अब मूल दस्तावेजों के बजाय उनकी फोटोकॉपी के आधार पर सुनवाई आगे बढ़ेगी। भोपाल की विशेष अदालत में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने बताया कि मामले से जुड़े मूल शासकीय दस्तावेज रिकार्ड रूम में रखे थे, जिन्हें दीमक ने नष्ट कर दिया है। मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण ईओडब्ल्यू ने उनकी फोटोकॉपी को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाने का आवेदन दिया था। विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने आवेदन स्वीकार कर लिया है। ईओडब्ल्यू की ओर से अदालत को बताया गया कि वर्ष 2008 में जब मामले का चालान पेश किया गया था, तब मूल दस्तावेजों से ही मशीन के माध्यम से उनकी फोटोकॉपी तैयार कराकर अदालत में जमा की गई थी। चालान के साथ इन छायाप्रतियों की प्रतियां बचाव पक्ष को भी उपलब्ध कराई गई थीं। इसके बाद मूल दस्तावेज रिकार्ड रूम में सुरक्षित रखे गए थे। लंबे समय बाद रिकार्ड रूम में रखे दस्तावेज दीमक से नष्ट हो गए। अब उनके दोबारा मिलने की संभावना नहीं है।

बचाव पक्ष ने प्रामाणिकता पर उठाए सवाल

आरोपित पक्ष ने मूल दस्तावेज नष्ट होने पर आपत्ति जताई। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संदीप गुप्ता ने बताया कि रिकॉर्ड रूम में रखे कई महत्वपूर्ण मूल दस्तावेज दीमक खा गई है। ऐसे में अब उपलब्ध फोटोकॉपी के आधार पर ही मामले की सुनवाई होगी। बचाव पक्ष ने फोटोकापी की प्रामाणिकता और मूल दस्तावेजों के नष्ट होने की परिस्थितियों को लेकर भी सवाल उठाए। अदालत ने माना कि चालान पेश किए जाने के समय मूल दस्तावेजों से तैयार की गई छायाप्रतियां रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और उनकी प्रतियां बचाव पक्ष को पहले ही दी जा चुकी थीं। इसके आधार पर अदालत ने फोटोकॉपी को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में रिकार्ड में शामिल करने की अनुमति दे दी। मामले में विवेचक के शेष मुख्य परीक्षण के लिए 14 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की गई है।

16 में से पांच आरोपितों की हो चुकी मौत

यह मामला वर्ष 2008 से अदालत में लंबित है। करीब 18 साल की अवधि में 16 आरोपितों में से पांच की मौत हो चुकी है। इनमें अरुण गुप्ता, पी. प्रकाश राव, अरुण कुमार कालिया, रमेश दुबे और तुलसीदास अग्रवाल शामिल हैं। वर्तमान में वीसी दुबे, आशीष साहू, डॉ. एके श्रीवास्तव, योगेशचंद्र उपरीत, यूएस विजयवर्गीय, अशोक मिश्रा, ओपी सोनी, ओपी टिकरिया, अजय सेन, नितिन महिंद्रा और जावेद अख्तर के खिलाफ मामला चल रहा है। एक आरोपित राधा बैलानी फरार है।

78 कंप्यूटर और सर्वर की खरीदी में गड़बड़ी का आरोप

ईओडब्ल्यू के अनुसार वर्ष 2008 में व्यापमं द्वारा 78 कंप्यूटर और सर्वर खरीदे गए थे। जांच में आरोप लगाया गया था कि कंप्यूटरों की खरीदी बाजार मूल्य से करीब दोगुनी दर पर की गई। टेंडर प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी कर संबंधित फर्म को लाभ पहुंचाने का आरोप है। इससे सरकारी खजाने को करीब 43 लाख रुपये का नुकसान होने की बात जांच में सामने आई थी। शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू ने मामले की जांच की थी।

1232 करोड़ का फ्लाईओवर, एक ही साल में बदहाली

नीचे अवैध पार्किंग, पोस्टर और कचरा ऊपर चोरी होने लगी हैं लोहे की प्लेटें

जबलपुर, दोपहर मेट्रो

करीब 1232 करोड़ रुपये की लागत से तैयार और लगभग सात किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर को बने अभी एक साल ही हुआ है, लेकिन इसकी तस्वीर अब बदलने लगी है। फ्लाई ओवर के नीचे जहां खाली जगह को व्यवस्थित रखा जाना था, वहां कई जगह कब्जे नजर आ रहे हैं। कहीं वाहनों की पार्किंग के लिए बेरीकेडिंग कर दी गई है तो कहीं ठेले-टपरे लग रहे हैं। पियर पर पोस्टर और फ्लैक्स चिपके हैं। गार्डन में कचरा फैला है और शाम ढलने के बाद यहां नशा करने वालों की आवाजाही रहती है।

फ्लाईओवर के ऊपर भी स्थिति अलग नहीं है। रात में कई जगह कार और दोपहिया वाहन किनारे खड़े दिखाई देते हैं। लोगों के वाहन में बैठकर शराब पीने की शिकायतें हैं। रोशनी के लिए लगाए गए बिजली के पोल के नीचे लगे धातु के ढक्कन भी कई जगह गायब हैं। दमोहनाका रोटरी में लगी लोहे की प्लेटों में से कई उखड़ी हुई हैं। इससे सड़क पर गड्ढे और ऊबड़-खाबड़ हिस्से बन गए हैं।

दमोहनाका नगर निगम जोन कार्यालय की तरफ जाने वाली सर्विस लेन पर फ्लाई ओवर के नीचे रात में ठेले-टपरे लग जाते हैं। खाली जगह में दुकानें सजने से वाहन चालकों को निकलने के लिए कम जगह मिलती है। दमोह रोड की तरफ फ्लाई ओवर के नीचे बने गार्डन में भी लोग बैठकर खान-पान करते नजर आते हैं। आसपास पाउच, पालीथिन और खाने-पीने का कचरा बिखरा हुआ है। दमोहनाका चौराहे के चारों तरफ भी दुकानों का सामान सड़क की ओर तक फैला हुआ है। इससे चौराहे के आसपास पहले से मौजूद यातायात के बीच जगह कम पड़ती है।

मदन महल की तरफ पेट्रोल पंप के सामने फ्लाई ओवर के नीचे का हिस्सा बड़े वाहन शोरूम की पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां बेरीकेड लगाकर जगह घेर दी गई है। शोरूम के कर्मचारी अपने वाहन इसी हिस्से में खड़े करते हैं। रानीताल हनुमान मंदिर की तरफ उतरने वाले लेग के नीचे भी एक मार्ट के कर्मचारियों और ग्राहकों के वाहन खड़े दिखाई देते हैं। वाहन फ्लाई ओवर के नीचे से निकलकर अचानक सड़क पर आते हैं। इसी दौरान सामने से आने वाले वाहनों से टक्कर की स्थिति बनती है।

पियर पर चस्पा कर दिए पोस्टर और फ्लैक्स

फ्लाई ओवर के पियर भी प्रचार सामग्री से अछूते नहीं हैं। रानीताल क्षेत्र में एक दंत चिकित्सक के क्लीनिक का प्रचार करने वाला बड़ा बोर्ड पियर पर लगा है। भाजपा कार्यालय के सामने फ्लाई ओवर के नीचे फ्लैक्स लगाए गए हैं। दमोहनाका और मदन महल चौक के आसपास भी कई पियर और आसपास के हिस्सों में पोस्टर चिपके दिखाई देते हैं। फ्लाई ओवर के जिस हिस्से से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं, वहां जगह-जगह लगे पोस्टर और फ्लैक्स इसकी पूरी तस्वीर बदल रहे हैं।

पोल के ढक्कन भी ले गए चोर

फ्लाई ओवर के ऊपर रोशनी के लिए लगाए गए बिजली के पोल के नीचे लगे धातु के ढक्कन भी कई जगह नहीं हैं। पोल के निचले हिस्से खुले दिखाई देते हैं। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि धातु के ये ढक्कन चोरी कर कबाड़ में बेचे जाते हैं।

गार्डन में बैठते हैं नशा करने वाले

फ्लाई ओवर के नीचे बनाए गए हरे-भरे हिस्सों में दिन में लोग बैठते हैं, लेकिन शाम के बाद यहां नशा करने वालों की आवाजाही बढ़ जाती है। कुछ स्थानों पर खाली पाउच और अन्य सामग्री भी दिखाई देती है। गार्डन की देखरेख नहीं होने से कई जगह हरियाली के बीच गंदगी जमा है। फ्लाई ओवर शहर की बड़ी परियोजनाओं में शामिल है। करीब सात किलोमीटर लंबे इस फ्लाई ओवर के निर्माण पर 1232 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। एक साल के भीतर ही इसके नीचे और आसपास जिस तरह कब्जे, पार्किंग, पोस्टर, कचरा और चोरी की घटनाएं दिखाई दे रही हैं, उससे इसकी मौजूदा स्थिति साफ नजर आती है।

सीएम यादव ने उज्जैन को दी विकास की रफ्तार

173 करोड़ रुपए की सौगात से सिंहस्थ से पहले बदलेगा स्वरूप

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों के समान विकास के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। उज्जैन प्राचीन काल से व्यापार, संस्कृति और वैभव का केंद्र रहा है। यहां के नागरिकों ने हमेशा शहर के विकास में योगदान दिया है और आज भी विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए स्वैच्छिक सहयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रविवार को महाकाल महालोक, उज्जैन में आयोजित विकास कार्यों के भूमिपूजन एवं लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 173 करोड़ रुपए लागत के 15 विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में बड़े पैमाने पर विकास और सौंदर्यीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। महाकाल मंदिर क्षेत्र, शिप्रा नदी के घाटों और शहर की अधोसंरचना को बेहतर बनाया जा रहा है। इन कार्यों से श्रद्धालुओं, पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि उज्जैन को जल्द ही मेट्रो ट्रेन की सौगात भी मिलेगी।

महाकाल क्षेत्र में पार्किंग और घाटों का विकास

कार्यक्रम में 12 विकास कार्यों का भूमिपूजन और तीन कार्यों का लोकार्पण किया गया। भूमिपूजन किए गए प्रमुख कार्यों में गौशाला मार्ग से शिप्रा विहार मार्ग का निर्माण, महाकाल लोक क्षेत्र में पार्किंग सुविधा का विकास, श्री महाकाल मंदिर परिसर का विकास और क्षिप्रा नदी के घाटों का जीर्णोद्धार शामिल है। इन कार्यों से महाकाल क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवागमन और पार्किंग की व्यवस्था बेहतर होगी। नगर निगम उज्जैन के आठ प्रमुख कार्यों सहित स्मार्ट सिटी, पुलिस और पर्यटन विभाग के विभिन्न विकास कार्यों पर कुल 153.31 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उज्जैन स्मार्ट सिटी द्वारा महाकाल मंदिर के पीछे लैंडस्केपिंग का काम किया जाएगा। पुलिस विभाग द्वारा चिंतामण जवासिया में पुलिस आवास और उन्हेल में थाना भवन का निर्माण किया जाएगा।

औद्योगिक गलियारे से बढ़ेगा विकास

डॉ. यादव ने कहा कि इंदौर-भोपाल-जबलपुर तक औद्योगिक गलियारा विकसित किया जा रहा है। इससे प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उन्होंने बताया कि भोपाल के मास्टर प्लान का प्रारूप प्रकाशित किया जा चुका है। ग्वालियर को नई महानगरीय सिटी के रूप में विकसित करने के साथ टेलीकॉम सिटी के रूप में भी आगे बढ़ाया जा रहा है। कार्यक्रम में उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया, राज्यसभा सदस्य बालयोगी उमेशनाथ महाराज, सांसद डॉ. लता वानखेड़े और महापौर मुकेश टटवाल सहित जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में उज्जैन में विकास कार्यों को गति मिली है और सिंहस्थ को देखते हुए शहर को नए स्वरूप में तैयार किया जा रहा है।

पेंशनरों की मांगों पर सरकार की चुप्पी से आक्रोश, नवरात्रि बाद मंत्रालय का घेराव

भोपाल, दोपहर मेट्रो

पेंशनरों की लंबित मांगों का निराकरण नहीं होने से प्रदेशभर के पेंशनरों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन जिला शाखा भोपाल की शिवाजी नगर में हुई बैठक में सरकार से लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की गई। बैठक में सैकड़ों पेंशनरों ने भाग लेकर समस्याओं और मांगों पर चर्चा की।

जिला शाखा भोपाल के अध्यक्ष सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि पेंशनरों की कई महत्वपूर्ण मांगें लंबे समय से लंबित हैं। इनमें वेतन आयोग के 59 माह के एरियर्स का भुगतान, पेंशनरों और उनके परिवारों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करना तथा जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई राहत प्रदान करना प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि इन मांगों को लेकर शासन स्तर पर लगातार ध्यान आकर्षित कराया जा रहा है, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने से पेंशनरों में नाराजगी है। शर्मा ने कहा कि बैठक में पेंशनरों ने सरकार से मांगों का शीघ्र निराकरण कर उन्हें राहत देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि पेंशनर अपने अधिकारों और लंबित मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं।

नवरात्रि के बाद होगा व्यापक प्रदर्शन

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि शासन ने मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो नवरात्रि के बाद भोपाल में मंत्रालय के समक्ष व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा। शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित आंदोलन में अधिक से अधिक पेंशनरों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में उपस्थित पेंशनरों ने संगठन के आंदोलन को पूर्ण सहयोग देने और आगामी प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शामिल होने का संकल्प लिया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष आमोद कुमार सक्सेना ने की।

प्रदेश में एमबीबीएस की 520 सीटें बढ़ीं

भोपाल। मध्यप्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए इस साल अवसर बढ़ रहे हैं। मेडिकल काउंसिल ने चालू सत्र में एमबीबीएस की सीटों में बड़ी बढ़ोतरी की है। अभी जारी 2026-27 की एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स के अनुसार प्रदेश में 520 सीटें बढ़ाई गई हैं। अब प्रदेश में एमबीबीएस की कुल सीटों की संख्या बढ़कर 6120 हो गई है। सीटों में हुई कुल वृद्धि में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की तुलना में निजी कॉलेजों का हिस्सा अधिक है। जारी सीट मैट्रिक्स के अनुसार मध्यप्रदेश में 34 मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। इनमें 20 सरकारी और 14 निजी मेडिकल कॉलेज हैं। सरकारी कॉलेजों में पहले से एमबीबीएस की 2900 सीटें थीं, जिनमें 120 सीटें बढ़ाकर 3020 कर दी गई हैं। वहीं निजी में सीटों की संख्या 2700 से बढ़कर 3100 कर दी गई है।

3 अक्टूबर को भोपाल आ सकते हैं अमित शाह

भेल दशहरा मैदान में होगा पशुपालक सम्मेलन, चार राज्यों के सहकारिता मंत्रियों की बैठक भी प्रस्तावित

भोपाल, दोपहर मेट्रो

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को भोपाल आ सकते हैं। उनके संभावित दौरे को लेकर भेल दशहरा मैदान में पशुपालकों के बड़े सम्मेलन की तैयारी प्रस्तावित है। सम्मेलन में बड़ी संख्या में दुग्ध उत्पादकों के शामिल होने की संभावना है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश, गुजरात सहित चार राज्यों के सहकारिता मंत्रियों की बैठक भी प्रस्तावित बताई जा रही है।

मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को 'कृषक कल्याण वर्ष' के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसकी थीम 'समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश' रखी गई है। सरकार की ओर से कृषि के साथ पशुपालन, डेयरी, सहकारिता और कृषि आधारित उद्योगों पर भी फोकस किया जा रहा है। भोपाल में प्रस्तावित सम्मेलन में प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों और पशुपालकों को जोड़ा जाएगा। इसका फोकस डेयरी क्षेत्र को सहकारिता के माध्यम से मजबूत करने और पशुपालकों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने से जुड़े विषयों पर रहने की संभावना है।

पांच दिन चलेगी प्रदर्शनी

भेल दशहरा मैदान पर ही अमित शाह नए आपराधिक कानूनों पर केन्द्रित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। नवीन आपराधिक कानूनों पर आधारित यह प्रदर्शनी करीब पांच दिन चलेगी। 3 अक्टूबर से इसे आम नागरिकों के लिए खोला जाएगा। इसमें विद्यार्थियों, युवाओं, स्वयंसेवी संगठनों और आम लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने की तैयारी है। प्रदर्शनी में अलग-अलग विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे। प्रवेश द्वार और अन्य हिस्सों में मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और जनजातीय विरासत की झलक भी दिखाई जाएगी।

एमपी पुलिस में आरक्षण का पेच!

975 पद होल्ड, चयनित होने के बाद भी 366 अभ्यर्थियों ने नहीं की जॉइनिंग

भोपाल। उज्जैन में वर्ष 2028 में होने जा रहे सिंहस्थ के पहले पुलिस मुख्यालय पुलिस में आरक्षकों के सभी रिक्त पदों को भरने के प्रयास में है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी प्रतिवर्ष 7500 पदों पर भर्ती के मान से तीन वर्ष में आरक्षकों के 22,500 पद भरने के निर्देश दिए हैं।

वर्ष 2025 की परीक्षा में 7500 पदों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण 13 प्रतिशत पदों पर परिणाम रोका जा रहा है। इस तरह भर्ती में 975 पदों को छोड़कर 6525 पदों के लिए परीक्षा परिणाम जारी किए गए। इनमें 366 पदों पर अभ्यर्थियों ने ज्वॉइन ही नहीं किया था। इनमें 200 पदों को प्रतीक्षा सूची से भरा गया है। बचे पदों को अगली भर्ती में जोड़ा जाएगा।

9662 नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू

इसके अतिरिक्त इसी माह कर्मचारी चयन मंडल ने कुल 9662 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इनमें आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) के 7500 पद हैं। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026 और 2027 में कुल 18,834 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। बाकी पदों पर वर्ष 2027 में भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसमें सभी श्रेणी के आरक्षक, शीघ्र लेखक, उप निरीक्षक आदि पद शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक से लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तक के कुल एक लाख 26 हजार पद हैं, जिनमें 25,400 रिक्त हैं। सिंहस्थ वर्ष 2028 अप्रैल-मई में होना है।

मेट्रो एंकर — सात माह के बकाये को लेकर उठी आवाज

आयुष्मान भुगतान में देरी से निजी अस्पतालों पर बढ़ा आर्थिक दबाव

भोपाल, दोपहर मेट्रो

प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत उपचार करने वाले निजी अस्पतालों के लंबित भुगतान का मुद्दा एक बार फिर सामने आया है। भोपाल में निजी अस्पताल संचालकों, चिकित्सकों और विभिन्न चिकित्सा संगठनों की बैठक हुई, जिसमें योजना के पात्र मरीजों से जुड़े करीब सात माह से लंबित दावों का जल्द भुगतान करने की मांग उठाई गई।

बैठक में अस्पताल संचालकों ने कहा कि मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल पहले ही बड़ी राशि खर्च कर चुके हैं। उपचार के साथ दवाओं, आवश्यक जांच, शल्य चिकित्सा, चिकित्सा सामग्री और चिकित्सकों तथा कर्मचारियों के वेतन का खर्च अस्पतालों को वहन करना पड़ रहा है। ऐसे में लंबे समय से भुगतान अटकने के कारण निजी अस्पतालों पर लगातार आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। चिकित्सा संगठनों ने कहा कि केवल नए दावों का भुगतान करना पर्याप्त नहीं है। पुराने माध्यम से दर्ज किए गए लंबित दावों के साथ-साथ वर्तमान व्यवस्था में अटके दावों का भी समयबद्ध तरीके से निपटारा किया जाना चाहिए। अस्पताल संचालकों का कहना है कि भुगतान में लगातार देरी से अस्पतालों की दैनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। समय पर राशि मिलने से अस्पताल मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ अपने कर्मचारियों और अन्य आवश्यक खर्चों का नियमित भुगतान कर सकेंगे। बैठक में अस्पतालों की गुणवत्ता मान्यता से जुड़े नियमों पर भी चर्चा हुई। संगठनों ने राष्ट्रीय अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाता मान्यता को अनिवार्य करने के बजाय स्वैच्छिक और प्रोत्साहन आधारित व्यवस्था अपनाने की मांग की। चिकित्सा संगठनों के अनुसार मरीजों की सुरक्षा और उपचार की गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन अस्पतालों पर लागू होने वाले मानदंड उनकी क्षमता, संसाधनों और उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखकर व्यावहारिक बनाए जाने चाहिए।

लाइसेंस प्रक्रिया सरल करने के लिए एकल खिड़की व्यवस्था की मांग

अस्पतालों से जुड़े विभिन्न अनुमतियों और लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एकल खिड़की व्यवस्था लागू करने की मांग भी बैठक में उठाई गई। संगठनों का कहना है कि अलग-अलग विभागों में बार-बार प्रक्रिया पूरी करने से अस्पताल संचालकों का समय और संसाधन दोनों खर्च करने पड़ते हैं। एक ही स्थान से आवश्यक अनुमतियां मिलने पर व्यवस्था अधिक सरल और पारदर्शी हो सकती है। बैठक में चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई गई। संगठनों ने चिकित्सक संरक्षण कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की। उनका कहना है कि अस्पतालों में सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना जरूरी है, ताकि चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी बिना भय के मरीजों को सेवाएं दे सकें। बैठक में उठी मांगों के जरिए निजी अस्पताल संचालकों ने आयुष्मान योजना के लंबित भुगतान के साथ-साथ अस्पतालों से जुड़े प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए सरकार से त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा जताई।

जवाबदेही किसकी

लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ वोट डालने की तारीख नहीं है। उसकी शुरुआत मतदाता सूची से होती है। इसलिए जब उसी सूची को तैयार करने वाली संवैधानिक संस्था के भीतर से उसके कामकाज पर गंभीर आपत्तियां सामने आएं, तो इसे महज राजनीतिक विवाद कहकर टाल देना आसान रास्ता हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र के लिए पर्याप्त जवाब नहीं। एक रिपोर्ट के अनुसार, दो निर्वाचन आयुक्तों ने पिछले दस महीनों में कम-से-कम 14 बार चुनाव आयोग के फैसलों और प्रक्रियाओं पर लिखित आपत्तियां दर्ज कीं। इनमें नए मतदाताओं के पंजीकरण, नाम हटाने-जोड़ने और मतदाता सूची के डिजिटल सिस्टम तक पहुंच जैसे बुनियादी सवाल शामिल हैं। सबसे असहज सवाल यह है कि अगर आयोग के भीतर ही दो आयुक्तों को कुछ फैसलों की प्रक्रिया पर आपत्ति थी, तो उन आपत्तियों का निपटारा कैसे हुआ? क्या हर सवाल का लिखित जवाब दिया गया? क्या निर्णय प्रक्रिया और जिम्मेदारी का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जा सकता है? चुनाव आयोग जैसी संस्था के लिए इन सवालों से बचने की गुंजाइश आखिर कितनी होनी चाहिए? गोवा का मामला इस बहस को जमीन देता है। रिपोर्ट के मुताबिक 97 मतदाताओं को स्थानीय निर्वाचन अधिकारियों ने दस्तावेजों के आधार पर पात्र माना, लेकिन सॉफ्टवेयर में उनके मामलों को दर्ज करने की सुविधा समय पर उपलब्ध नहीं थी। बाद में गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने कहा कि कई मामलों में नाम जोड़े जा चुके हैं और बाकी मामलों की प्रक्रिया चल रही है। यहां सवाल केवल 97 नामों का नहीं है। सवाल उस व्यवस्था का है जिसमें जमीन पर मौजूद वैधानिक अधिकारी किसी नागरिक को पात्र मान ले, लेकिन डिजिटल व्यवस्था उसके निर्णय को दर्ज ही न कर पाए। तब अंतिम फैसला अधिकारी का होगा या सॉफ्टवेयर का? चुनाव आयोग ने कहा है कि पिछले एक वर्ष के उसके निर्णय सर्वसम्मति से हुए हैं और आंतरिक मतभेद निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा हैं। लेकिन यही तो जवाबदेही की कसौटी है-यदि सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ है, तो हर आपत्ति का तथ्यात्मक और दस्तावेजी जवाब सामने रखने में संकोच कैसा? मतदाता सूची की सफाई जरूरी है, लेकिन सफाई के नाम पर पात्र नागरिक की आवाज दबनी नहीं चाहिए।

चुनाव आयोग में तलवारबाजी कांग्रेस की ही देन, अब इसी पर खड़ा कर रही सियासी सवाल

आलोक मेहता
वरिष्ठ पत्रकार

चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल के साथ पिछले वर्षों के दौरान हुए चुनावों में हेराफेरी के आरोपों ने सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्था को अनावश्यक रूप से संदेहास्पद बना दिया है। राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी को ऐसा विश्वास क्यों है कि चुनाव आयोग के आयुक्तों के बल पर ही चुनावी जीत-हार होती है? कुछ तो है, जिस आधार पर राहुल गांधी दो कथित असंतुष्ट चुनाव आयुक्तों को महान राष्ट्र भक्त बताते हुए यह दावा भी कर रहे हैं कि वह लगातार चुनाव आयोग की अंदरूनी जानकारी पाते रहे हैं।

उनकी बात का मतलब चुनाव आयुक्तों की तलवारबाजी में पर्दे के पीछे कांग्रेसी नेताओं की अहम भूमिका है। अन्यथा संवैधानिक नियम-अधिकार के तहत चुनाव आयुक्त अपनी आपत्तियां राष्ट्रपति को भेजने के बजाय कैबिनेट सचिव को नहीं भेजते रहते। और तब राहुल गांधी को लड़ने की कमान नहीं मिलती। इस घटनाक्रम में चुनाव आयुक्तों के राजनीतिक उपयोग पर बहस के दौरान चुनाव सुधारों के लिए मशहूर शेषन और जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति तथा जी.एस. गिल की याद ताजा हो जाती है। संयोग से जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति से मेरा अच्छा परिचय था और पद से रिटायर होने के बाद दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में वह अपने अनुभव बड़े उत्साह और हंसी-खुशी से मुझे सुनाते थे। वह दिल्ली में रहते हुए हैदराबाद के अखबार डेक्कन क्रॉनिकल के सलाहकार सदस्य और कानूनी मामलों के कॉलमिस्ट बन गए थे और बार-बार कहते थे कि वह भी पत्रकार हैं। वह गौरव के साथ बताते थे कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से उनके कितने गहरे सम्बन्ध थे और शेषन को काबू में करने के लिए कैसे उन्हें चुनाव आयुक्त बनाया और शेषन से टकराने में कितना आनंद आया।

जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति, जिन्हें आम तौर पर जी.वी.जी. के नाम से जाना जाता था, पेशे और प्रशिक्षण से वकील थे। हैदराबाद में वकालत करने के साथ-साथ उन्होंने स्थानीय लॉ कॉलेज में अध्यापन भी किया। शिवराज पाटिल, जो आगे चलकर केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष बने, उनके प्रतिष्ठित विद्यार्थियों में शामिल थे। दिल्ली के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में वे कृष्ण मेनन और दामोदरम संजीवय्या जैसे दिग्गजों के करीबी सहयोगी के रूप में सक्रिय रहे। कांग्रेस सरकार में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान पहले जी.वी.जी. प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के करीबी रहे। एक अवसर पर इंदिरा गांधी ने उन्हें भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी भेजा था। हालांकि, राजीव गांधी सरकार के दौरान उन्हें हाशिये पर कर दिया गया और विधि आयोग में सदस्य-सचिव के पद पर भेज दिया गया। भोपाल गैस त्रासदी के बाद उन्होंने उस कानूनी टीम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा दिलाने के लिए अमेरिकी अदालतों में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड के खिलाफ मुकदमा लड़ा था।

जी.वी.जी. नरसिंह राव के अच्छे मित्र थे और उनकी मित्रता हैदराबाद के दिनों से चली आ रही थी। दोनों साथ-साथ दिल्ली आए थे और पचास के दशक के अंतिम वर्षों में हाईकोर्ट में वकील के रूप में पंजीकृत हुए थे। जी.वी.जी. के अनुसार, प्रणब मुखर्जी और कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने पी.वी. पर दबाव बनाया कि मुझे शेषन को रोकने के लिए भेजा जाए।' दिलचस्प बात यह है कि निर्वाचन सदन में प्रवेश करने से पहले तक जी.वी.जी. और शेषन अच्छे मित्र थे। दोनों परिवारों के बीच भी अच्छे संबंध थे। संगीत के प्रति प्रेम के अलावा दोनों परिवार सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी एक-दूसरे के करीब थे।

चुनाव आयोग के विवाद 1990 के बाद शुरू हुए। टी.एन. शेषन 12 दिसंबर 1990 को मुख्य चुनाव आयुक्त बने। चुनाव आयोग की शक्तियों का बहुत आक्रामक ढंग से इस्तेमाल करते हुए उन्होंने आचार संहिता बनाई और चुनावी गड़बड़ियों और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। शेषन अपने पद की संवैधानिक शक्ति की बहुत व्यापक व्याख्या कर रहे थे। नरसिंह राव सरकार और टी.एन. शेषन के बीच टकराव

बढ़ता गया। शेषन के कड़े चुनावी फैसलों और उनकी स्वतंत्र कार्यशैली से सरकार तथा कांग्रेस के हित कई बार प्रभावित हुए। 1 अक्टूबर 1993 को कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रपति के अध्यादेश के माध्यम से चुनाव आयोग को तीन सदस्यीय बनाया और एम.एस. गिल तथा जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति को नियुक्त किया। इससे शेषन की अकेली निर्णायक शक्ति समाप्त होकर बहुमत-आधारित व्यवस्था बन गई। अध्यादेश में यह व्यवस्था की गई कि यदि तीनों के बीच किसी विषय पर सहमति न बने तो बहुमत का फैसला प्रभावी होगा। यानी चुनाव आयोग के पास किसी मुद्दे पर अकेले अंतिम निर्णय लेने की स्थिति नहीं रहती। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री राव और कांग्रेस के वफादार जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति चुनाव आयुक्त के रूप में, 1 अक्टूबर 1993 से 30 सितंबर 1999 तक, मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन की कथित 'तानाशाही' के सामने मजबूती से खड़े होकर उनका मुकाबला किया। शेषन अपनी कार्यशैली और बोलने के अंदाज के कारण 'अल्सेशियन' के नाम से चर्चित थे। आरोप था कि वे अपने साथी चुनाव आयुक्तों से हिसाब चुकता करने के लिए बेहद निचले स्तर तक चले जाते थे। एक बार तो उन्होंने कथित तौर पर उनके टेलीफोन की लाइन तक कटवा दी थी।

शेषन ने बाद में स्वयं आरोप लगाया था कि उनके कई फैसलों से कांग्रेस सरकार असहज हो गई थी। उन्होंने कुछ उपचुनावों को स्थगित किया, मॉडल कोड के उल्लंघन पर कार्रवाई की और कई मामलों में सत्तारूढ़ दल की राजनीतिक सुविधा को महत्व नहीं दिया। शरद पवार और प्रणब मुखर्जी से जुड़े उपचुनावों को स्थगित करने तथा तमिलनाडु के अण्णिपेट विधानसभा क्षेत्र के चुनाव को लेकर भी विवाद हुए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस नेतृत्व उनसे असहमत था। उनके अनुसार, दिल्ली चुनाव टालने का अनुरोध भी किया गया था, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। शेषन ने 1993 में इस अध्यादेश और नियुक्तियों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 14 जुलाई 1995 को सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत चुनाव आयोग को बहु-सदस्यीय बनाना संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप है। कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान ने चुनाव आयोग को किसी एक व्यक्ति के बजाय 'आयोग' के रूप में स्थापित किया है।

जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति की जमीनी स्तर पर व्यक्तिगत संबंध और संवाद स्थापित करने की क्षमता ने उन्हें नरसिंह राव के बाद के दौर में जम्मू-कश्मीर में स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव कराने में मदद की। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव को व्हिप से मुक्त रखने का निर्णय जी.वी.जी. का एक स्थायी योगदान माना जाता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था– 'व्हिप स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अनुकूल नहीं है।' 1997 में गठबंधन राजनीति के शुरुआती दौर में उनके इस रुख से राजनीतिक दल नाराज हो गए थे, लेकिन वे अपने निर्णय पर कायम रहे। उन्होंने साफ किया कि राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने वाले मतदाता यानी सांसद और विधायक किसी खास उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा जारी व्हिप के माध्यम से बाध्य नहीं किए जा सकते। उनका यह निर्णय बाद में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का हिस्सा बन गया।

इसके बाद भी आयोग में मतभेद के कई मामले सामने आए। एन. गोपालस्वामी और नवीन चावला के बीच विवाद से लेकर 2019 में अशोक लवासा और सुनील अरोड़ा के बीच मतभेद तक, अलग-अलग दौर में आयोग के अंदर की खींचतान सार्वजनिक होती रही है। इन अनुभवों को ध्यान में रखकर पिछले वर्ष से चुनाव आयोग में टकराव की चिंगारी लगा राहुल गांधी ने मोदी सरकार और सम्पूर्ण चुनावी व्यवस्था के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों के दौरान कम से कम 14 मौकों पर कुछ फैसलों और आदेशों को लेकर औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई। उनका दावा था कि कुछ फैसले और आदेश उनकी जानकारी के बिना जारी किए गए। इन आपत्तियों में वैधानिक मतदाता पंजीकरण फॉर्म-6 में बदलाव और मतदाता सूची के डेटाबेस के केंद्रीकृत नियंत्रण जैसे मुद्दे शामिल बताए गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि विचारों में अंतर किसी भी विचार-विमर्श का सामान्य हिस्सा है और अंतिम फैसले, जिसमें विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर से जुड़े फैसले भी शामिल हैं, सर्वसम्मति से लिए गए हैं। संधू और जोशी ने अपने नाम से जुड़ी इन आपत्तियों पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की। वहीं विपक्षी दलों ने एसआईआर के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने और सत्तारूढ़ भाजपा के पक्ष में काम करने के आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग ने अब इन आरोपों को दोबारा खारिज कर दिया। 26 सितंबर को चुनाव आयोग के प्रमुख सहित तीनों सदस्यों की बैठक हुई। बैठक के बाद संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के सभी महत्वपूर्ण निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। लेकिन लगता है कि इस विवाद का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पद पर बने रहने तक कांग्रेस और उसके सहयोगी बारूद की तरह उपयोग करते रहेंगे।

-यह लेखक के अपने विचार हैं।

पति-पत्नी के विवाद में बच्चों और पॉक्सो कानून का दुरुपयोग रोकना जरूरी

मनोज कुमार अग्रवाल
स्तंभकार

वैवाहिक विवादों और बच्चों की कस्टडी के मुकदमों में पॉक्सो कानून के कथित दुरुपयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने कहा है कि इस गंभीर कानून का इस्तेमाल दबाव बनाने या कानूनी बढ़त हासिल करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक और बच्चों की कस्टडी से जुड़े विवादों में पॉक्सो कानून के कथित दुरुपयोग को रोकने के लिए गुरुवार को गाइडलांस जारी किए हैं। ऐसे मामले में कोर्ट ने कहा कि नाबालिग से यौन अपराध के मामले में पॉक्सो एफआइआर दर्ज होने मात्र से आरोपी को तत्काल गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पुलिस को गिरफ्तारी से पहले कानून में निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य दिशानिर्देश और नियम-वैवाहिक कलह से जुड़े पॉक्सो मामलों में पुलिस अब तुरंत या रूटीन गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी। गिरफ्तारी से पहले किसी बाल मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक द्वारा बच्चे का मूल्यांकन करना अनिवार्य किया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि बच्चे पर कोई दबाव या ट्यूटरिंग सिखाया पढ़ाया जाना तो नहीं की गई है। ये सुरक्षा उपाय तभी लागू होंगे जब पॉक्सो का आरोप उसी घर में रहने वाले किसी माता-पिता या परिजन पर हो और उनके बीच पहले से वैवाहिक विवाद चल रहा हो।

बता दें कि वैवाहिक विवादों और कस्टडी की जंग में बच्चों का इस्तेमाल मोहरे की तरह किए जाने का चलन भारतीय समाज और न्याय प्रणाली के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर सामने आयी है। पति-पत्नी के आपसी मनमुटाव, अहंकार और बदले की भावना जब इस सीमा तक बढ़ जाए कि अपने ही बच्चे के यौन शोषण का झूठा आरोप दूसरे पक्ष पर मड़ दिया जाए, तो यह न केवल कानून का घोर दुरुपयोग है, बल्कि बच्चे के मानसिक व भावनात्मक स्वास्थ पर भी गहरा आघात है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी.विश्वनाथन की पीठ ने इस बढ़ती प्रवृत्ति पर बेहद गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय का यह ऐतिहासिक निर्णय बच्चों के अधिकार, न्याय व्यवस्था की साख और बेकसूर माता-पिता के सम्मान की रक्षा की दिशा में एक बेहद संतुलित और स्वागत योग्य कदम है। वैवाहिक विवादों में पॉक्सो कानून के दुरुपयोग पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एक कानूनी व्यवस्था में सुधार का प्रयास नहीं, बल्कि परिवार, समाज और न्याय व्यवस्था के लिए गंभीर चेतावनी भी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संवेदनशील पहलू को ध्यान में रखते हुए वैवाहिक विवादों से जुड़े पॉक्सो मामलों में गिरफ्तारी और जांच के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय निर्धारित किए हैं। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने एक वैवाहिक विवाद से उत्पन्न मामले में पिता के विरुद्ध दर्ज पॉक्सो प्राथमिकी रद्द करते हुए देशभर के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच में आरोपों की पुष्टि नहीं हुई थी। अदालत ने बच्ची की कानूनी अभिरक्षा पिता के पास रहने तथा विशेषज्ञों की सहायता से पिता-पुत्री के संबंधों को पुनः स्थापित करने का निर्देश दिया। इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि कानून का उद्देश्य न्याय दिलाना है, किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करना नहीं। बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया पॉक्सो अधिनियम अत्यंत महत्वपूर्ण कानून है। लेकिन जब इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत दुश्मनी, बदले की भावना या बच्चे की अभिरक्षा हासिल करने के साधन के रूप में किया जाता है, तब वास्तविक पीड़ितों के हितों को भी नुकसान पहुंचता है। एक अभिभावक पर पॉक्सो का का आरोप लगते ही दूसरे पक्ष को कानूनी बढ़त मिल सकती है। आरोपित व्यक्ति को सामाजिक अपमान, मानसिक पीड़ा और लंबी अदालती प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। यदि बाद में आरोप निराधार साबित हों, तब भी खोई हुई प्रतिष्ठा और टूटे हुए पारिवारिक संबंधों की भरपाई आसान नहीं होती। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे अधिक उपेक्षित पक्ष स्वयं बच्चा होता है। जिस उम्र में उसे माता-पिता का स्नेह, सुरक्षा और विश्वास मिलना चाहिए, उसी उम्र में उसे पुलिस, अदालत, पूछताछ और परस्पर विरोधी आरोपों का सामना करना पड़ता है। कई बार वह यह समझने की स्थिति में भी नहीं होता कि उसके आसपास आखिर हो क्या रहा है। ऐसे अनुभव उसके मन पर स्थायी प्रभाव छोड़ सकते हैं। इसलिए न्यायालय द्वारा स्वतंत्र विशेषज्ञ मूल्यांकन की व्यवस्था अत्यंत प्रासंगिक है। बच्चे की बात बिना दबाव, भय अथवा किसी पक्ष के प्रभाव के सुनी जानी चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि उसे बार-बार पूछताछ और अनावश्यक मानसिक तनाव से न गुजरना पड़े। विशेषज्ञ की रिपोर्ट जांच में सहायक होगी, लेकिन अंतिम निर्णय अन्य उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों के आधार पर ही किया जाएगा। पॉक्सो अधिनियम की धारा 22 में कुछ परिस्थितियों में झूठी शिकायत अथवा गलत जानकारी देने पर दंड का प्रावधान है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की चिंता उचित है कि दंडात्मक कार्रवाई होने तक निर्दोष व्यक्ति को गंभीर क्षति पहुंच चुकी हो सकती है। इसलिए केवल बाद में दंड देने की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, शुरुआती स्तर पर विवेकपूर्ण जांच और कानूनी सावधानियां भी आवश्यक हैं। इस निर्णय के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस अधिकारियों, बाल संरक्षण इकाइयों, मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों और न्यायिक संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय जरूरी होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी जिलों की जिला बाल संरक्षण इकाइयों को पोक्सो नियम, 2020 के तहत विशेषज्ञों के रजिस्टर को अपडेट करने का निर्देश दिया। रिमांड और जमानत पर सुनवाई करने वाली अदालतों को यह भी देखना होगा कि जांच अधिकारी ने इन सुरक्षा उपायों का पालन किया या नहीं।

-यह लेखक के अपने विचार हैं।

निशाना

उजड़ा सारा बाग फक़ीरे

रामकिशोर नाविक

जाग फक़ीरे
भाग फक़ीरे
बोल रहे हैं
काग फक़ीरे
उजड़ा सारा
बाग फक़ीरे
मुश्क़िल रोटी
साग फक़ीरे
सच में है तू
नाग फक़ीरे
नहीं धुलेंगे
दाग़ फक़ीरे
छोड़ पुराना
राग फक़ीरे
तू है कितना
घाग फक़ीरे
खूब मनाली
फाग फक़ीरे।

टेक्नो - अपडेट

पुणे के कपल ने बना दी देश की पहली नमक वाली बैटरी, धूप से होगी चार्ज, इस्तेमाल शुरू

मोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन और सोलर पावर स्टोरेज में अब तक लिथियम-आयन बैटरियों का दबदबा रहा है, लेकिन पुणे के एक रिसर्चर दंपती ने इसका विकल्प तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पुणे के डीप-टेक स्टार्टअप Rechargion Energy ने 1 किलोवॉट-आवर क्षमता वाली सोडियम-आयन बैटरी विकसित की है। इसे आम बोलचाल में 'नमक वाली बैटरी' कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें लिथियम की जगह सोडियम का इस्तेमाल होता है। इसकी खासियत यह है कि इसे सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली से चार्ज किया जा सकता है। इसकी तकनीक का व्यावहारिक इस्तेमाल हैदराबाद के सीआईआई गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर में शुरू हो चुका है।

सूरज की रोशनी बनेगी बैटरी की ताकत: हैदराबाद के सेंटर की छत पर लगे सोलर पैनल दिन में सूर्य की रोशनी से बिजली बनाते हैं। यही बिजली 1 kWh सोडियम-आयन बैटरी में स्टोर होती है। जरूरत पड़ने पर बैटरी से इस ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। मौजूदा सिस्टम में संग्रहित बिजली से सेंटर के बाहर लगा बड़ा डिस्प्ले रोशन किया जा रहा है। खास बात यह है कि सिस्टम को डीसी पावर के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे बिजली को बार-बार एसी में बदलने की जरूरत कम होती है और पावर लॉस भी घटता है। लिथियम-आयन बैटरियों की सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए जरूरी महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति है। सोडियम इसके मुकाबले ज्यादा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और भारत में सोडियम क्लोराइड यानी नमक का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होता है। Rechargion की तकनीक में कोबाल्ट और निकेल का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। कंपनी का लक्ष्य ऐसी बैटरी तकनीक तैयार करना है, जिसमें भारत की आयात पर निर्भरता कम हो। नीति आयोग के Frontier Tech नेटवर्क के अनुसार कंपनी के सेल ने 110-120 Wh/kg ऊर्जा घनत्व हासिल किया है और इन्हें सोलर स्टोरेज, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तथा ग्रिड स्टोरेज जैसे क्षेत्रों के लिए विकसित किया जा रहा है।

इस तकनीक को रिसर्चर दंपती डॉ. विलास शेळके और डॉ. मंजूषा शेळके ने विकसित किया है। कंपनी की शुरुआत 2021 में हुई और यह CSIR-नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, पुणे से निकला स्पिन-ऑफ है। 2024 में कंपनी ने सोडियम-आयन सेल बनाने के लिए पायलट प्लांट शुरू किया। इसके बाद सेल को ARAI के सुरक्षा परीक्षणों से भी गुजारा गया। कंपनी ने हार्ड-कार्बन आधारित एनोड और अपने विकसित इलेक्ट्रोड मैटेरियल पर काम किया है।

सोलर स्टोरेज से ई-बाइक और ड्रोन तक: सोडियम-आयन बैटरी का इस्तेमाल केवल सोलर ऊर्जा स्टोरेज तक सीमित नहीं है। कंपनी ने इलेक्ट्रिक साइकिल में लिथियम बैटरी के स्थान पर सोडियम-आयन बैटरी का इस्तेमाल करके प्रदर्शन किया है। ड्रोन जैसे अनुप्रयोगों में भी तकनीक का परीक्षण किया गया है। हालांकि सोडियम-आयन बैटरियों की ऊर्जा घनत्व अभी कई लिथियम-आयन बैटरियों से कम है, इसलिए हर तरह के इलेक्ट्रिक वाहन में इनका इस्तेमाल तुरंत संभव नहीं माना जा सकता।

वायरल-कंटेंट

गांव वालों का कमाल, 9000 बोतलों से बच्चों के लिए बनाया इको क्लास रूम

मिस्र के एक गांव में बच्चों के सामने समस्या थी कि स्कूल दूर होने की वजह से उन्हें रोज लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। अब वहां एक ऐसा क्लासरूम तैयार किया गया है, जिसने बच्चों की पढ़ाई को आसान बनाने के साथ-साथ गांव में बढ़ते प्लास्टिक कचरे की समस्या का भी एक अलग तरीके से समाधान निकाला है। यह कहानी मिस्र के फायूम इलाके के एजबेट इशाक गांव की है। यहां तैयार किए गए इको क्लासरूम की सबसे खास बात यह है कि इसकी दीवारों के निर्माण में 9 हजार से ज्यादा इस्तेमाल की जा चुकी प्लास्टिक बोतलों का इस्तेमाल किया गया है। इन बोतलों में रेत भरकर उन्हें निर्माण का हिस्सा बनाया गया।

होलसिम फाउंडेशन के मुताबिक, जब इस प्रोजेक्ट की योजना बनाई गई थी, तब एजबेट इशाक एक ग्रामीण कृषि गांव था, जहां करीब 1,000 लोग रहते थे। गांव में पर्याप्त शैक्षणिक सुविधाएं नहीं थीं। इसलिए बच्चों को पढ़ाई के लिए नजदीकी स्कूल तक जाने के लिए रोज 2 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करना पड़ता था। परेशानी सिर्फ दूरी की नहीं थी। रास्ते का एक बड़ा हिस्सा व्यस्त सड़क से होकर गुजरता था और सड़क की हालत भी अच्छी नहीं थी। ऐसे में बच्चों के लिए रोज स्कूल आना-जाना आसान नहीं था। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों ने महंगी और पूरी तरह नई निर्माण सामग्री पर निर्भर रहने के बजाय गांव में उपलब्ध चीजों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। क्लासरूम की दीवारों में 9 हजार से ज्यादा प्लास्टिक बोतलों को रेत से भरकर लगाया गया। इसके अलावा स्थानीय मिट्टी से बने ब्लॉक, बांस और प्राकृतिक मिट्टी का भी इस्तेमाल हुआ। पास में गिराए गए एक पुराने क्लिनिक से मिले टूटे कंक्रीट और दोबारा इस्तेमाल किए गए बलुआ पत्थर को भी इमारत की नींव में लगाया गया।

इस क्लासरूम को बनाने में सिर्फ प्लास्टिक की बोतलों का ही दोबारा इस्तेमाल नहीं हुआ। पुराने दरवाजों और खिड़कियों को ठीक करके दोबारा लगाया गया। फेंके गए लकड़ी के पैलेट से बच्चों के लिए डेस्क और बेंच बनाए गए। फर्श पर प्राकृतिक मिट्टी का इस्तेमाल किया गया, जबकि छत को बनाने के लिए बांस लगाया गया। इतना ही नहीं, पानी को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए एक खास वेस्टवॉटर सिस्टम भी लगाया गया, जिससे पानी को लैंडस्केपिंग में इस्तेमाल किया जा सके।

रिजर्व की सीमा लांघ जंगल तलाश रहे बाघ, कॉरिडोर बचाना अब नई चुनौती

वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में बढ़ी बाघों की संख्या, युवा बाघ गांवों और खेतों की ओर कर रहे मूवमेंट, मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने वन अमले की बढ़ी निगरानी

तेंदूखेड़ा। दोपहर मेट्रो

मध्यप्रदेश में बाघों की बढ़ती संख्या के साथ अब उनके सुरक्षित आवागमन और मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकना वन विभाग के लिए नई चुनौती बन गया है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 30 से अधिक पहुंचने के बाद युवा बाघ नए क्षेत्र की तलाश में रिजर्व की सीमा से बाहर निकल रहे हैं। ये बाघ कई बार गांवों, खेतों और वन सीमाओं से गुजरते हैं। वन अमला उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखते हुए संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा रहा है।

सितंबर 2023 में अधिसूचित यह प्रदेश का सातवां और देश का 55वां टाइगर रिजर्व है। इसका क्षेत्र नर्मदा घाटी तक फैला है और यह पन्ना व सतपुड़ा टाइगर लैंडस्केप के बीच महत्वपूर्ण वन्यजीव कॉरिडोर का काम करता है। यहां सागौन, साजा, धौरा, बेर और आंवला के जंगलों में तेंदुआ, भेड़िया, लकड़बग्घा, सियार, सांभर, चीतल, नीलगाय और चिंकारा भी पाए जाते हैं। वन्यजीव कॉरिडोर पर सड़क-रेल परियोजनाओं, हाईटेंशन लाइन, कृषि विस्तार, बढ़ती आबादी और अतिक्रमण का दबाव बढ़ रहा है। इससे बाघों के पारंपरिक मार्ग प्रभावित हो रहे हैं और आबादी वाले क्षेत्रों से गुजरने का खतरा बढ़ा है। कोर क्षेत्र के 93 गांवों में से 44 का करीब 600 करोड़

रुपए की लागत से पुनर्वास हो चुका है, जबकि शेष 49 गांवों के पुनर्वास की योजना पर काम जारी है। विभाग अब बाघ संरक्षण के साथ सुरक्षित कॉरिडोर और ग्रामीणों के सह-अस्तित्व पर जोर दे रहा है। वहीं इस मामले में रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्वके डीएफओ रजनीश कुमार ने बताया कि 'बाघों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी है। सुरक्षित कॉरिडोर विकसित करने, मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने और स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाने पर फोकस है।

वन्यजीवों के लिए महत्वपूर्ण है इलाका

वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नर्मदा घाटी के विस्तृत वन क्षेत्र में फैला है और पन्ना तथा सतपुड़ा टाइगर लैंडस्केप के बीच महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। घने जंगल बाघों सहित कई वन्यजीवों को प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराते हैं। सागौन, साजा, धौरा, बेर और आंवला के जंगलों में तेंदुआ, भेड़िया, लकड़बग्घा, सियार, सांभर, चीतल, नीलगाय और चिंकारा जैसे वन्यजीव पाए जाते हैं। बाघों की बढ़ती संख्या के साथ इन जंगलों से जुड़े प्राकृतिक मार्गों को सुरक्षित रखना जरूरी हो गया है। सड़क, रेल, बिजली लाइन और कृषि विस्तार से कॉरिडोर पर दबाव बढ़ने के कारण वन विभाग निगरानी और गश्त बढ़ा रहा है। टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में शामिल 93 गांवों में से 44 का पुनर्वास करीब 600 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जा चुका है। अब शेष 49 गांवों के चरणबद्ध पुनर्वास की योजना पर काम चल रहा है। पुनर्वास से वन्यजीवों को अधिक निर्बाध प्राकृतिक आवास मिलने की उम्मीद है, वहीं ग्रामीणों को सड़क, शिक्षा और आजीविका जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। बाघों की आवाजाही बढ़ने से खेतों में काम करने वाले किसानों और वनोपज संग्रह करने वालों को भी सतर्क रहना पड़ रहा है।

न्यूज विंडो

पितृपक्ष : गोरैया घाट पर उमड़ा आस्था का सैलाब, विधि-विधान से की पूजा

तेंदूखेड़ा। पितृपक्ष के प्रथम दिन रविवार को गोरैया नदी घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। नगर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपने पूर्वजों का तर्पण करने घाट पहुंचे। सुबह से दोपहर तक श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। लोगों ने नदी में स्नान कर पितरों को जल अर्पित किया और विधि-विधान से तर्पण एवं अन्य धार्मिक कर्मकांड संपन्न किए। पंडित भारत प्रसाद अवस्थी ने श्रद्धालुओं को तर्पण की धार्मिक विधि कराई। श्रद्धालुओं ने पितरों की आत्मा की शांति और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। पितृपक्ष में पूर्वजों के निमित्त तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने की परंपरा है। लगातार बारिश के चलते इस बार गोरैया नदी का जलस्तर सामान्य से अधिक रहा और पानी का बहाव भी तेज रहा। इसके बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कमी नहीं दिखी। आगामी दिनों में भी तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने की संभावना है।

सड़कों पर रेत-गिट्टी के ढेर, शाम को मवेशियों का कब्जा, हादसों को न्योता दे रहे मुख्य मार्ग

तेंदूखेड़ा। नगर की प्रमुख सड़कों पर निर्माण सामग्री के ढेर और शाम होते ही मवेशियों का जमावड़ा यातायात के लिए परेशानी का कारण बन गया है। कई स्थानों पर रेत, गिट्टी, ईंट और लोहे के सरिए सड़क तक फैले होने से मार्ग संकरे हो गए हैं। रात में सामग्री दिखाई नहीं देने से दुर्घटना का खतरा भी बढ़ रहा है। दमोह-जबलपुर मार्ग पर गुरैया नदी से हाईस्कूल तक, बस स्टैंड से हाईस्कूल और माहुला पुल की ओर जाने वाले मार्ग सहित दमोह, सागर और तारादेही मार्ग पर कई जगह यही स्थिति है। इन मार्गों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में वाहन और यात्री बसें गुजरती हैं। इसके अलावा दुकानदारों द्वारा सड़क तक सामान फैलाने और वाहनों को बेतरतीब खड़ा करने से भी आवागमन बाधित हो रहा है। तहसील कार्यालय से एक्सीलेंस स्कूल तक और चौरई मार्ग पर शाम के समय मवेशियों का जमावड़ा रहता है। अचानक सड़क पर आने वाले मवेशियों से वाहन चालकों को ब्रेक लगाना पड़ता है। नगरवासियों मिथिलेश, रुपेश, सोनू, रत्नेश और गोपाल ने निर्माण सामग्री हटवाने, अतिक्रमण व अव्यवस्थित पार्किंग पर कार्रवाई तथा सड़कों से मवेशियों का जमावड़ा हटाने की मांग की है।

गौसेवा से शुरू हुआ युवाओं का सेवा संकल्प झलौन गौशाला में पशु आहार कराया

तेंदूखेड़ा। ग्राम झलौन स्थित गौशाला में बजरंग दल से जुड़े नवगठित युवा सदस्यों ने गौसेवा के साथ अपने सेवा कार्यों की शुरुआत की। युवाओं ने गौशाला पहुंचकर गायों के लिए केला, ब्रेड, खरी, बिनौला, चूनी, आटा और रोटियों सहित अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई। इसके बाद युवाओं ने अपने हाथों से गायों को पशु आहार कराया। युवा सदस्यों ने कहा कि गौसेवा के माध्यम से सेवा कार्यों की शुरुआत की गई है। उनका उद्देश्य आगे भी पशु सेवा के साथ समाजहित और सर्वहित से जुड़े कार्यों में सक्रिय सहभागिता करना है। इस दौरान सदस्यों ने नियमित रूप से गौसेवा, पशु सेवा और जरूरतमंदों की सहायता जैसे कार्यों से जुड़े रहने का संकल्प लिया। साथ ही अन्य युवाओं को भी समाजसेवा के लिए प्रेरित करने की बात कही। सदस्यों ने बताया कि बजरंग दल की समिति का औपचारिक गठन अभी नहीं हुआ है, लेकिन युवाओं ने सेवा गतिविधियां शुरू कर दी हैं। आगामी दिनों में गौशाला में नियमित सेवा कार्यों के साथ अन्य सामाजिक गतिविधियां संचालित करने का प्रयास किया जाएगा। सेवा कार्य में ईशान जैन, सत्यम नामदेव, राज दत्ता, सतीश सेन, लकी तिवारी, अभिषेक ठाकुर, सतेंद्र, चंदू, मौसम, रीतेश, प्रियांश, अनुज, ब्रजेश, परिउल, राघवेंद्र सहित आदि मौजूद थे।

तहसील परिसर में रोज पहुंचते हैं सैकड़ों ग्रामीण, महिलाओं-बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी

14 लाख रुपए खर्च के बाद भी 3 साल से अधूरा शौचालय कॉम्प्लेक्स, खुले में निस्तार की मजबूरी

तेंदूखेड़ा। दोपहर मेट्रो

तहसील कार्यालय परिसर में आमजन की सुविधा के लिए नगर परिषद द्वारा करीब 14 लाख रुपए से अधिक की लागत से शुरू कराया गया शौचालय कॉम्प्लेक्स तीन साल बाद भी अधूरा पड़ा है। वर्ष 2023 में शुरू हुआ निर्माण अब तक पूरा नहीं हो सका है और करीब 50 प्रतिशत काम शेष बताया जा रहा है। निर्माण अधूरा होने से तहसील में विभिन्न कार्यों के लिए पहुंचने वाले ग्रामीणों, महिलाओं, बुजुर्गों और फरियादियों को शौचालय सुविधा नहीं मिल पा रही है।

तहसील परिसर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। शौचालय की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को खुले में निस्तार करना पड़ रहा है। इससे परिसर के आसपास गंदगी फैलने की स्थिति बनी हुई है। महिलाओं और बुजुर्गों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों के अनुसार निर्माण कार्य शुरू होने के बाद कुछ समय में ही काम बंद हो गया था। लंबे समय से अधूरा पड़ा भवन अब देखरेख के अभाव में खराब होने लगा है। भवन की कुछ दीवारों में दरारें भी दिखाई देने लगी हैं। लोगों का कहना है कि समय रहते काम पूरा नहीं हुआ तो सरकारी राशि से बना भवन और क्षतिग्रस्त हो सकता है। अधूरा भवन गंदगी के बीच पड़ा होने से इसके असामाजिक तत्वों का अड्डा बनने की आशंका भी जताई जा रही है। याचिका लेखकों और स्थानीय लोगों ने नगर परिषद व जिला प्रशासन से निर्माण जल्द पूरा कराने की मांग की है। वहीं इस मामले में एसडीएम सीजी गोस्वामी ने बताया कि मेरे संज्ञान में बात आई है। मुझे जानकारी नहीं थी कि यह शौचालय निर्माण है। मैं जानकारी लेकर पता करता हूं कि काम क्यों बंद है और अधूरा क्यों पड़ा है।

महिलाओं-बुजुर्गों को ज्यादा दिक्कत

तहसील कार्यालय में राजस्व सहित अन्य कामों के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्रामीण और फरियादी पहुंचते हैं। इनमें महिलाओं और बुजुर्गों की संख्या भी रहती है। परिसर में शौचालय की सुविधा नहीं होने के कारण लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। कई लोगों को खुले में निस्तार के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे परिसर के आसपास गंदगी फैल रही है। आमजन का कहना है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यदि निर्माण जल्द पूरा कर शौचालय को उपयोग में लाया जाए तो ग्रामीणों को राहत मिल सकती है और परिसर में स्वच्छता भी बनी रहेगी।

देखरेख के अभाव में खराब हो रहा निर्माण, असामाजिक तत्वों का भी खतरा

करीब तीन साल से अधूरा पड़ा शौचालय कॉम्प्लेक्स अब देखरेख के अभाव में खराब होने लगा है। स्थानीय लोगों के अनुसार भवन की कुछ दीवारों में दरारें दिखाई देने लगी हैं। लंबे समय से काम बंद होने के कारण परिसर में गंदगी भी जमा हो रही है। लोगों को आशंका है कि यदि भवन को जल्द पूरा कर उपयोग में नहीं लाया गया तो यह असामाजिक तत्वों का अड्डा बन सकता है। इससे तहसील परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। स्थानीय लोगों और याचिका लेखकों ने नगर परिषद तथा जिला प्रशासन से निर्माण कार्य में देरी के कारणों की जांच कर जल्द काम पूरा कराने की मांग की है।

भगत सिंह जयंती पर युवाओं ने श्रमदान से चमक उठा गौरैया घाट

तेंदूखेड़ा। दोपहर मेट्रो

शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती के अवसर पर रविवार को साथी क्लब तेंदूखेड़ा के युवाओं ने गौरैया घाट पर स्वच्छता अभियान चलाकर श्रमदान किया। गणेश उत्सव के समापन के बाद घाट एवं आसपास के क्षेत्र में बिखरी पूजा सामग्री और कचरे को एकत्रित कर सफाई की गई। युवाओं ने घाट की रंगाई-पुताई का कार्य भी किया।

अभियान के दौरान युवाओं ने घाट पर पड़ी प्लास्टिक बोतलें, पॉलीथिन, थर्माकोल, फूल-माला सहित अन्य अपशिष्ट हटाए। घाट के आसपास सफाई कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया। क्लब सदस्यों ने बताया कि गणेश उत्सव के बाद पितृपक्ष शुरू हो चुका है। ऐसे में लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से युवाओं ने स्वयं श्रमदान किया। क्लब सदस्यों ने कहा कि धार्मिक आयोजनों के साथ प्राकृतिक जलस्त्रोतों और उनके आसपास की स्वच्छता बनाए रखना भी समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। भगत सिंह की जयंती पर सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य के माध्यम से समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने का प्रयास किया गया।

आजादी के बाद भी विकास से दूर सारसबगली का वार्ड-6, बारिश में कीचड़ में तब्दील रास्ते

पंचायत को शिकायत के बाद भी नहीं हुआ स्थायी समाधान

तेंदूखेड़ा। दोपहर मेट्रो

सरकार और प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता एवं विकास के दावे कर रहे हैं, लेकिन जनपद पंचायत के ग्राम सारसबगली के वार्ड क्रमांक 6 में हालात इन दावों से अलग नजर आ रहे हैं। बारिश के बाद वार्ड की सड़कें कीचड़ और गंदे पानी से सराबोर हो गई हैं। जगह-जगह जलभराव होने से ग्रामीणों का आवागमन मुश्किल हो गया है। कई स्थानों पर घुटनों तक कीचड़ और पानी जमा होने से लोगों को इसी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है।

सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को उठानी पड़ रही है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए कीचड़ भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश शुरू होते ही वार्ड की सड़कों की स्थिति बिगड़ जाती है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से पानी लंबे समय तक रास्तों पर जमा रहता है।

शिकायतों के बाद भी नहीं बदले हालात

ग्रामीणों के अनुसार वार्ड की समस्या से सरपंच और सचिव को कई बार अवगत कराया जा चुका है। इसके बावजूद समस्या के स्थायी समाधान के लिए अब तक ठोस पहल नहीं हुई। सड़क निर्माण और जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से हर साल बारिश में ग्रामीणों को इसी समस्या का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से वार्ड का निरीक्षण कर सड़क निर्माण, नाली एवं जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है। उनका कहना है कि बुनियादी सुविधाओं के अभाव में रोजमर्रा का आवागमन प्रभावित हो रहा है। समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बारिश के दौरान जलभराव, गंदगी और आवागमन की परेशानी और बढ़ सकती है।

मेट्रो एंकर हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी, देशभक्ति गीतों के बीच शहीद को किया नमन

तिरंगे के साथ गूंजा 'इंकलाब जिंदाबाद', भगत सिंह की जयंती पर यात्रा

तेंदूखेड़ा। दोपहर मेट्रो

शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती के अवसर पर रविवार को नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों ने हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में सहभागिता की और शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश की एकता व अखंडता का संदेश दिया।

कार्यक्रम की शुरुआत विश्राम भवन ग्राउंड से हुई। यहां शहीद भगत सिंह के चित्र पर तिलक लगाकर एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस के प्रमुख पदाधिकारियों ने भगत सिंह के जीवन और उनके विचारों पर प्रकाश डाला। इसके बाद कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। डीजे पर बज रहे देशभक्ति गीतों के बीच कार्यकर्ता 'इंकलाब जिंदाबाद' और 'भगत सिंह अमर रहें' के नारे लगाते हुए

आगे बढ़े। यात्रा के दौरान नगर का माहौल देशभक्ति से ओत-प्रोत रहा। युवाओं सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। आयोजकों ने कहा कि भगत सिंह का जीवन और उनके विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं। उनके विचारों को आत्मसात करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। तिरंगा यात्रा का समापन रेस्ट हाउस के पास किया गया। यात्रा में यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यश घनगौरिया, पूर्व विधायक प्रताप सिंह लोधी, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष दृगपाल सिंह लोधी, जिला पंचायत सदस्य रजनी ठाकुर, महिपाल सिंह लोधी, जनपद अध्यक्ष तुलाराम यादव, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नीलेश यादव, मंडलम अध्यक्ष प्रमोद बेन सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी मौजूद रहे।

यात्रा में दिखा युवाओं का उत्साह

भगत सिंह जयंती पर निकाली गई तिरंगा यात्रा में युवाओं की विशेष भागीदारी रही। हाथों में तिरंगा लेकर कार्यकर्ता नगर के प्रमुख मार्गों से निकले और देशभक्ति गीतों के बीच शहीद भगत सिंह के जयकारे लगाए। 'इंकलाब जिंदाबाद' और 'भगत सिंह अमर रहें' के नारों से नगर गूंजता रहा। आयोजकों ने कहा कि भगत सिंह ने देश के लिए त्याग और समर्पण की मिसाल कायम की। उनके विचार युवाओं को देशहित में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यात्रा के माध्यम से देश की एकता, अखंडता और तिरंगे के सम्मान का संदेश भी दिया गया। स्थानीय लोगों ने भी यात्रा का उत्साहपूर्वक स्वागत किया।

खंडवा में 65 कनेक्शन पर 9 लाख बकाया, गांव में 3 महीने से बिजली गुल

बिल जमा नहीं हुआ तो कंपनी ने ट्रांफॉर्मर भी ठीक नहीं कराया, नतीजा...बिल जमा करने वाले पांच घर भी प्रभावित

खंडवा। दोपहर मेट्रो

छैगांवमाखन जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम खजूरी में पिछले करीब तीन महीने से बिजली सप्लाई बंद है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव का ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद बिजली कंपनी ने बकाया बिजली बिल का हवाला देकर उसे सुधरवाया नहीं। इसके बाद पूरे गांव की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई। अब खेतों की बिजली सप्लाई भी बंद कर दी गई है। ऐसे में गांव के घरों के साथ खेतों में भी अंधेरा है। ग्रामीणों के मुताबिक, पिछले तीन महीने से बिजली नहीं होने के कारण उन्हें रोजमर्रा के कामों में परेशानी उठानी पड़ रही है। इस दौरान राखी और गणेश उत्सव भी गांव के लोगों ने अंधेरे में ही मनाए। ग्रामीणों का कहना है, बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन अलग-अलग काटे जाने चाहिए थे। जो परिवार नियमित रूप से बिल जमा कर रहे हैं, उन्हें सामूहिक कार्रवाई का खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए।

5 परिवार नियमित बिल जमा कर रहे

ग्रामीण विनोद चौहान ने बताया कि करीब तीन महीने पहले गांव का ट्रांसफार्मर खराब हो गया था। उस समय बिजली कंपनी की ओर से गांव पर बिजली बिल का बकाया होने की बात कही गई। बकाया राशि जमा नहीं होने के कारण ट्रांसफार्मर को सुधारा नहीं गया और धीरे-धीरे पूरे गांव की बिजली सप्लाई बंद हो गई।

वहीं बिजली कंपनी के लाइनमैन शिवनारायण कुशवाह के अनुसार, खजूरी गांव में करीब 70 कनेक्शनधारी हैं। इनमें से केवल 5 परिवार नियमित रूप से बिजली बिल जमा करते हैं, जबकि करीब 65 कनेक्शनधारियों पर लगभग 9 लाख रुपए की बकाया राशि है।

आदिवासी परिवारों पर करीब 40-40 हजार बकाया

बिजली कंपनी के अनुसार, गांव में करीब 40 से 50 परिवार आदिवासी हैं। इन उपभोक्ताओं पर करीब 40-40 हजार रुपए तक का बिजली बिल बकाया बताया जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक, कई परिवारों ने कनेक्शन लेने के बाद से नियमित रूप से बिजली बिल जमा नहीं किया। कंपनी का कहना है कि लंबे समय से बिल जमा नहीं होने और बड़ी बकाया राशि के कारण गांव की बिजली सप्लाई बंद करने की कार्रवाई की गई है। सप्लाई बंद होने के बाद अब कुछ उपभोक्ता बकाया राशि जमा कराने के लिए आगे आ रहे हैं।

ग्रामीण बोले- सभी पर कार्रवाई करना गलत

ग्रामीणों का कहना है कि बिजली बिल की वसूली करना कंपनी का अधिकार है, लेकिन कार्रवाई का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे नियमित बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को परेशानी न हो। उनका कहना है कि जिन लोगों ने लंबे समय से बिल नहीं भरा है, उनके कनेक्शन काटे जाएं या उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। पूरे गांव की बिजली बंद करने से उन परिवारों को भी परेशानी हो रही है, जो समय पर बिल जमा करते रहे हैं। बिजली नहीं होने से घरों में पंखे, बल्ब, मोबाइल और अन्य जरूरी उपकरण बंद पड़े हैं।

मुरैना में चंबल की रेत के अवैध परिवहन का मामला

पुलिस को देख गलियों में दौड़ीं रेत से भरी 20 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां, कार को मारी टक्कर

मुरैना। दोपहर मेट्रो

चंबल नदी से अवैध रेत उत्खनन और परिवहन का मामला रविवार सुबह एक बार फिर सामने आया। करीब 5.35 बजे रेत से भरी लगभग 20 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम को देखकर टंच रोड और राठौर कॉलोनी की ओर तेज रफ्तार में भागने लगीं। इसी दौरान राठौर कॉलोनी में एक ट्रैक्टर ने सड़क किनारे खड़ी कार को टक्कर मार दी। टक्कर से कार नाली में जा घुसी। भागते ट्रैक्टरों की चपेट में आने से एक घर के बाहर रखा लकड़ी का काउंटर और नल की लाइन भी टूट गई। घटना के दो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं।

स्थानीय निवासी नरेश राठौर के अनुसार वह सुबह धौलपुर से लौटकर गली में पहुंचा ही था, तभी रेत से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉलियां तेज रफ्तार में आती दिखीं। एक ट्रैक्टर ने उनकी कार को टक्कर मार दी। उनके मुताबिक पीछे पुलिस वाहन और पुलिसकर्मी भी थे। उनका कहना है कि सुबह का समय होने से गली में भीड़ नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। डीएफओ हरिशचंद्र बघेल ने बताया कि टास्क फोर्स, पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम अवैध रेत के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉलियां रिहायशी क्षेत्र में भाग गईं, इसलिए उन्हें पकड़ा नहीं जा सका। सिटी कोतवाली टीआई अमित सिंह भदौरिया ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगालकर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और चालकों की पहचान की जा रही है। स्थानीय लोगों ने कहा- भीड़ होती तो हो सकता था बड़ा हादसा

रविवार सुबह राठौर कॉलोनी में अचानक तेज रफ्तार से गुजरती रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के कारण लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय निवासी कमला बाई ने बताया कि सुबह शोर सुनकर बाहर आने पर कई ट्रैक्टर-ट्रॉलियां तेज गति से भागती दिखाई दीं। इसी दौरान एक ट्रैक्टर ने नरेश राठौर की कार को टक्कर मार दी। लोगों के अनुसार भारी वाहनों के रिहायशी इलाके से इस तरह गुजरने के कारण बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रही।

पीछा किया तो सड़क पर ही रेत पलटी

संयुक्त टीम द्वारा पीछा किए जाने के दौरान रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के चालकों ने बचने के लिए तेज रफ्तार से वाहन दौड़ाए। बताया गया कि इसी दौरान एक चालक ने सड़क पर ही ट्रॉली से रेत पलट दी और फिर वाहन को रिहायशी गलियों की ओर भगा ले गया। पुलिस और वन विभाग की टीम ने ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे गलियों में निकल गए। इस दौरान क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक भारी वाहनों का इस तरह रिहायशी क्षेत्र में तेज गति से गुजरने से दुर्घटना का खतरा बढ़ गया था। मामले में छ्छड्ड फुटेज के आधार पर वाहनों और उनके चालकों की पहचान की जा रही है।

सीएम डॉ. यादव के नरसिंहपुर दौरे से पहले कांग्रेस ने तैयार किया जनहित का एजेंडा

मेडिकल-कृषि-इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर किसान भुगतान, फसल मुआवजा, सीवर सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं तक उठाएगी मुद्दे

नरसिंहपुर। दोपहर मेट्रो

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 30 सितंबर को प्रस्तावित नरसिंहपुर दौरे को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिले से जुड़े विभिन्न जनहित के मुद्दों को सामने रखने की तैयारी की है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल पूर्व में की गई घोषणाओं की प्रगति, किसानों की समस्याओं और शहर की व्यवस्थाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा।

संगठन प्रभारी दीवान शैलेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री से पूर्व स्वीकृत योजनाओं का बजट, वर्तमान स्थिति और कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा स्पष्ट करने की मांग की जाएगी। कांग्रेस नेताओं ने मेडिकल कॉलेज, कृषि महाविद्यालय और इंजीनियरिंग कॉलेज की घोषणाओं की वर्तमान स्थिति स्पष्ट करने की मांग रखी है। कांग्रेस गन्ना किसानों के बोनस और लंबित भुगतान का मुद्दा भी उठाएगी। नेताओं ने गन्ने पर 50 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा पर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने तथा आगामी सीजन में रिकवरी के आधार पर खरीदी मूल्य तय करने की मांग की है। अतिवृष्टि और मौसम से प्रभावित उड़द, सोयाबीन सहित अन्य फसलों के नुकसान का सर्वे कर फसल बीमा व मुआवजा देने की मांग भी की जाएगी। शहर में सीवर परियोजना से क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण, कचरा उठाव और नालियों की सफाई व्यवस्था सुधारने की मांग रखी जाएगी। जिला अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों तथा स्वास्थ्य केंद्रों में रिक्त पद भरने का मुद्दा भी उठेगा। कांग्रेस प्रवक्ता आशीष गुप्ता और अजय दुबे ने कहा कि पूर्व घोषणाओं की विभागवार प्रगति रिपोर्ट और लंबित कार्यों की समय-सीमा सार्वजनिक की जानी चाहिए। कांग्रेस के अनुसार, मुख्यमंत्री के समक्ष इन मुद्दों का समयबद्ध समाधान कराने की मांग रखी जाएगी।

सोने की खरीद में बिलिंग पर उठे सवाल, जांच की मांग

शहडोल। उमरिया, अनूपपुर और शहडोल जिलों में सोने के कारोबार को लेकर बिलिंग व्यवस्था और वास्तविक बिक्री कीमत के संबंध में सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि कुछ मामलों में सोने की वास्तविक बिक्री कीमत और ग्राहक को दिए गए बिल में दर्ज राशि में अंतर हो सकता है। ऐसे में ग्राहक हितों के साथ बिलिंग और कर व्यवस्था की पारदर्शिता को लेकर जांच की मांग की जा रही है। सोने की खरीदारी के समय बिल में वजन, शुद्धता, प्रति ग्राम दर, मेकिंग चार्ज, अन्य शुल्क, लागू जीएसटी और कुल भुगतान की स्पष्ट जानकारी दर्ज होना जरूरी है। वास्तविक लेन-देन और बिल में दर्ज राशि में अंतर होने की स्थिति में इसकी निगरानी किस स्तर पर हो रही है, यह भी जांच का विषय बताया गया है। तीनों जिलों के आभूषण प्रतिष्ठानों की बिलिंग व्यवस्था की जांच कर वास्तविक बिक्री मूल्य और बिल में दर्ज राशि का मिलान कराने की मांग की गई है। साथ ही ग्राहकों को नियमानुसार बिल उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। ग्राहकों से भी सोना खरीदते समय बिल लेकर वजन, शुद्धता, दर, मेकिंग चार्ज, जीएसटी और कुल राशि का मिलान करने की अपील की गई है।

न्यूज विंडो

बेटी के जन्म पर खुशियों का उपहार नवजात बेटियों को बांटे कपड़े

गंजबासौदा। अंतरराष्ट्रीय बेटी दिवस के अवसर पर स्थानीय शासकीय अस्पताल में नवजात बेटियों को कपड़े वितरित कर उनके स्वस्थ और उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। यह पहल 'बेटियों को जीने दो' समूह द्वारा की गई। समूह प्रमुख दीपसिंह कुशवाह ने सिविल अस्पताल के शिशु वार्ड में जन्मी नवजात बेटियों की जानकारी लेकर उनके परिजनों को कपड़े भेंट किए। कुशवाह ने बताया कि बेटी के जन्म पर निःशुल्क कपड़े देने की पहल 2 सितंबर 2021 को उनकी बेटी भूमि कुशवाह के चौथे जन्मदिन से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य बेटियों के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना और उनके जन्म को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने बताया कि अब तक निजी खर्च से मध्यप्रदेश सहित देश के 10 राज्यों में 2408 से अधिक जोड़ी कपड़े बेटियों को वितरित या भेजे जा चुके हैं। इनमें नई दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरप्रदेश शामिल हैं।

औबेदुल्लागंज में शासकीय जमीन की रजिस्ट्री पर सवाल, मिलीभगत के आरोपों से मचा हड़कंप

वार्ड-4 की बेशकीमती भूमि पर फर्जी कब्जा और रिकॉर्ड तैयार करने का आरोप; कलेक्टर से निष्पक्ष जांच और रजिस्ट्री निरस्त करने की मांग

औबेदुल्लागंज। दोपहर मेट्रो

नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 4 में बेशकीमती शासकीय भूमि की निजी नाम पर रजिस्ट्री कराए जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय नागरिकों ने मामले में अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कलेक्टर रायसेन एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी को शिकायत सौंपी है। शिकायत में पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है।

शिकायतकर्ताओं के अनुसार, संबंधित भूमि का उपयोग सार्वजनिक पार्क और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए किया जाता रहा है। जमीन पर नगर परिषद द्वारा बाउंड्रीवॉल भी बनवाई गई थी। उनका दावा है कि भूमि पर पहले किसी व्यक्ति का निजी कब्जा नहीं था, इसके बावजूद फर्जी कब्जा दर्शाकर निजी नाम पर रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कथित कब्जे को सही साबित करने के लिए फर्जी रसीदें और मनगढ़ंत मकान रिकॉर्ड तैयार किए गए। शिकायतकर्ताओं का यह भी आरोप है कि रजिस्ट्री औबेदुल्लागंज के बजाय रायसेन जाकर कराई गई, जिससे पूरे मामले की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने प्रकरण की स्वतंत्र एवं उच्चस्तरीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। साथ ही कथित रूप से कराई गई रजिस्ट्री को निरस्त कर भूमि को शासन के नाम सुरक्षित रखने और मामले में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि शासकीय भूमि से जुड़े इस मामले में दस्तावेजों की जांच, भूमि के वास्तविक स्वामित्व और रजिस्ट्री की प्रक्रिया की निष्पक्ष पड़ताल से ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

किताबों से निकलकर संविधान की पाठशाला पहुंचे विद्यार्थी, दिल्ली में जाना लोकतंत्र का मर्म

गंजबासौदा। दोपहर मेट्रो

श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा 25 एवं 26 सितंबर को विद्यार्थियों का दो दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण दिल्ली में आयोजित किया गया। विभागाध्यक्ष डॉ. भास्कर दुबे के नेतृत्व में 22 विद्यार्थियों और शिक्षकों के दल ने देश की प्रमुख राजनीतिक एवं संवैधानिक संस्थाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया। भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान के साथ संवैधानिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली से परिचित कराना था। दल ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति भवन का भ्रमण किया। विद्यार्थियों ने न्यायपालिका की भूमिका, संवैधानिक व्यवस्था तथा राष्ट्रपति पद के महत्व को समझा। इसके अलावा राजघाट, इंडिया गेट और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का भी भ्रमण किया। यात्रा के दौरान नई दिल्ली स्थित सामाजिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र में राजनीति विज्ञान के प्रख्यात विद्वान डॉ. राजीव भार्गव से विद्यार्थियों ने संवाद किया। विद्यार्थियों ने लोकतंत्र, संविधान और समकालीन राजनीति से जुड़े प्रश्न पूछे, जिनका उन्होंने विस्तार से उत्तर दिया। विद्यार्थियों के ठहरने की व्यवस्था मध्य प्रदेश भवन में की गई। यात्रा को सफल बनाने में महाविद्यालय शिक्षा समिति, प्रबंधन समिति और प्राचार्य डॉ. पीयूष दुबे का विशेष सहयोग रहा।

मेट्रो एंकर दमोह स्टेशन पर यात्रियों को उतारकर सपेरों और रेलवे टीम ने की सघन सर्चिंग, सीट-बर्थ के नीचे तलाश के बाद भी नहीं मिला सांप

संपर्क क्रांति के एसी कोच में घुसा सांप, आधे घंटे चली सर्चिंग

दमोह?। दोपहर मेट्रो

जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बी-3 एसी थ्री-टियर कोच में रविवार रात सांप दिखाई देने की सूचना से यात्रियों में हड़कंप मच गया। एक यात्री ने कोच में सांप देखने की जानकारी दी, जिसके बाद कई यात्री अपनी सीट छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर चले गए।

ट्रेन रात करीब 10.15 बजे दमोह रेलवे स्टेशन पहुंची। सूचना मिलते ही रेलवे टीम के साथ सपेरों को बुलाया गया और सुरक्षा के लिहाज से बी-3 कोच के यात्रियों को कुछ देर के लिए बाहर उतार दिया गया। इसके बाद कोच में सांप की तलाश शुरू की गई। टीम ने सीटों के नीचे, बर्थ के आसपास और कोच के अन्य हिस्सों में सघन सर्चिंग की। करीब 35 मिनट तक चली तलाश के बावजूद सांप का पता नहीं चल सका। इस दौरान कोच के यात्रियों में दहशत और असमंजस की स्थिति बनी रही। बर्थ नंबर 41 और 42 को खाली कराकर यात्रियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। जांच पूरी होने के बाद ट्रेन को आगे रवाना कर दिया गया। रात करीब 10.52 बजे ट्रेन दमोह स्टेशन से रवाना हुई। यात्रियों के बीच यह सवाल बना रहा कि सांप वास्तव में कोच में आया था या सूचना के बाद किसी अन्य हिस्से में चला गया। जीआरपी सहायता केंद्र प्रभारी जुम्मन शेख ने बताया कि सूचना मिलने पर सपेरों और रेलवे टीम के साथ कोच की सर्चिंग कराई गई, लेकिन सांप नहीं मिला। बर्थ 41 और 42 के यात्रियों को दूसरी जगह शिफ्ट कर ट्रेन रवाना कर दी गई।

सीटों के नीचे और बर्थ के आसपास तलाश

संपर्क क्रांति के बी-3 कोच में सांप दिखाई देने की सूचना मिलते ही रेलवे अमला सतर्क हो गया। दमोह स्टेशन पहुंचते ही सुरक्षा के लिहाज से कोच के यात्रियों को बाहर उतारा गया। इसके बाद सपेरों और रेलवे कर्मचारियों ने सीटों के नीचे, बर्थ के आसपास, कोच के कोनों और अन्य संभावित स्थानों पर सांप की तलाश शुरू की। करीब 35 मिनट तक सर्चिंग चलने के बावजूद सांप नहीं मिला। इस दौरान यात्रियों में डर का माहौल बना रहा। विशेष रूप से बर्थ नंबर 41 और 42 के यात्रियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। जांच पूरी होने के बाद यात्रियों को सुरक्षित तरीके से आगे की यात्रा के लिए रवाना किया गया। सांप दिखाई देने की सूचना के बाद संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस रविवार रात करीब 10.15 बजे दमोह रेलवे स्टेशन पहुंची। सूचना मिलते ही रेलवे टीम और सपेरों को बुलाया गया। बी-3 एसी कोच में यात्रियों को बाहर उतारकर सर्चिंग शुरू की गई। करीब 35 मिनट तक चली जांच में सांप नहीं मिला।

कार्यालय थाना प्रभारी थाना गौतम नगर जिला भोपाल

क्र/थाना/गौतमनगर/अप./क्र. 580/26 दिनांक 23/9/26

जाहिर सूचना

सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि थाना गौतम नगर के अपहृत आशी सोनी पिता शारदा प्रसाद सोनी उम्र 21 साल निवासी म.न. जनता 97 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी एलआइजी नारियल खेड़ा थाना गौतम नगर भोपाल दिनांक 15.09.26 के 10/30 बजे के लगभग घर से पीजीबीटी कॉलेज से टी सी लेने जा रही हूं बोलकर गई है। जो अभी तक आशी कॉलेज से घर वापस नहीं आई। मोबाइल न. 6260120885 लेकर गई है मो. बंद है की सूचना पर अपराध क्र 580/26 कायम कर जांच में लिया गया।

गुमशुदा का हुलिया रंग सावला कद 5 फिट 3 करलर का जींस लाईट ग्रीन रंग की कुर्ती पहने है, पांव में सेंडिल पहने है, गले में सोने की चैन पहनी है, कान में टाप्स पहने है, बाल लंम्बे है। सामने सिर पर पिम्पल है। सूचना मिलने पर थाना गौतम नगर, व प्रआर 604 बालाराम के मो.नं. 07552730830, 9685815070 पर सूचित करें।

थाना प्रभारी
थाना गौतमनगर भोपाल

जी-19131/26

'अभी काम खत्म नहीं हुआ...

विश्व कप को लेकर रोहित का बड़ा संकेत, बोले- आगे देखने के लिए हमेशा कुछ होता है

नई दिल्ली, एजेंसी

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 2027 वनडे विश्व कप को लेकर अपने भविष्य के संकेत दिए हैं। टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके रोहित फिलहाल वनडे प्रारूप में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले उन्होंने साफ किया कि क्रिकेट में उनके लिए अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। उनके बयान से 2027 विश्व कप में खेलने की उम्मीदों को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

जियोस्टार से बातचीत में रोहित शर्मा ने कहा कि उनके मन में कभी यह विचार नहीं आया कि उन्होंने क्रिकेट में जो करना था, वह पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा, यह विचार मेरे दिमाग में कभी नहीं आएगा कि जो काम मुझे करना था, वह खत्म हो गया है। रोहित के मुताबिक जब तक कोई खिलाड़ी मैदान पर सक्रिय है, उसके सामने हमेशा कुछ नया हासिल करने का लक्ष्य रहता है। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने और बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश जारी रहती है।

2027 विश्व कप का इंतजार

2027 वनडे विश्व कप को लेकर रोहित ने अपनी उत्सुकता भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जब तक वह खेल रहे हैं, तब तक आगे देखने के लिए कुछ न कुछ जरूर रहेगा। रोहित ने कहा, मैं विश्व कप का इंतजार कर रहा हूं और देख रहा हूं कि मेरे लिए आगे क्या है। उनके इस बयान को 2027 विश्व कप में उनकी संभावित भागीदारी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, उन्होंने सीधे तौर पर यह घोषणा नहीं की कि वह विश्व कप में निश्चित रूप से खेलेंगे।

आईसीसी टूर्नामेंट की चुनौती अलग

रोहित ने आईसीसी टूर्नामेंट और सामान्य द्विपक्षीय सीरीज के बीच अंतर पर भी बात की। उनके मुताबिक विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में अलग-अलग टीमों और अलग-अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में खिलाड़ियों को अपनी तैयारी और रणनीति में बदलाव करना होता है।

2023 में खिताब से रह गए थे दूर

रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने 2023 वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया था। हालांकि, अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार के बाद भारत का खिताब जीतने का सपना टूट गया था। अब 2027 विश्व कप रोहित के लिए उस अधूरे अभियान को आगे बढ़ाने का मौका हो सकता है। 2027 वनडे विश्व कप अक्टूबर-नवंबर में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित होना है। रोहित टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन वनडे में अभी सक्रिय हैं। विराट कोहली भी 2027 विश्व कप को अपने करियर का आखिरी विश्व कप बता चुके हैं। ऐसे में यदि दोनों दिग्गज भारतीय टीम का हिस्सा रहते हैं, तो एक बार फिर बड़े मंच पर उनकी जोड़ी पर सबकी नजरें रहेंगी।

नए चीफ सेलेक्टर को सुनील गावस्कर की दो टूक चेतावनी

अच्छे फैसले भुला दिए जाएंगे, एक गलती याद रहेगी

नई दिल्ली, एजेंसी

भारतीय क्रिकेट में जल्द ही चयन समिति की कमान बदल सकती है। पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर का कार्यकाल समाप्त होने के करीब है और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) उनके उत्तराधिकारी की तलाश में जुटा है। इसी बीच भारत के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने नए मुख्य चयनकर्ता की जिम्मेदारी संभालने वाले व्यक्ति को इस चुनौतीपूर्ण पद की हकीकत से पहले ही आगाह कर दिया है।

सुनील गावस्कर ने अपने कॉलम में मुख्य चयनकर्ता के पद को प्रतिष्ठित होने के साथ-साथ बेहद मुश्किल जिम्मेदारी बताया। उनके मुताबिक चयनकर्ताओं को लगातार खिलाड़ियों के चयन, टीम से बाहर रखने और उपलब्ध स्थानों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। ऐसे में लिए गए फैसलों से खिलाड़ियों और प्रशंसकों की नाराजगी भी सामने आ सकती है। गावस्कर ने लिखा कि इस पद पर बैठने वाले व्यक्ति की पीठ पर हमेशा एक तरह का 'निशाना' रहता है। चयनकर्ता के कई अच्छे फैसले समय के साथ भुला दिए जाते हैं, लेकिन एक गलत या विवादित फैसला लंबे समय तक चर्चा में रहता है। गावस्कर ने चयन समिति के अध्यक्ष की स्थिति की तुलना अंपायरिंग, विकेटकीपिंग और कमेंट्री जैसी भूमिकाओं से की। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में किए गए कई अच्छे काम पीछे छूट जाते हैं और किसी एक गलती को जरूरत से ज्यादा महत्व मिल जाता है। यही स्थिति मुख्य चयनकर्ता के साथ भी होती है। उनकी टिप्पणी का संकेत यही था कि नए मुख्य चयनकर्ता को फैसले लेते समय यह समझना होगा कि हर निर्णय सभी को पसंद आए, यह संभव नहीं है। इसलिए पद संभालने वाले व्यक्ति को आलोचना का सामना करने के लिए भी तैयार रहना होगा।

हर फैसला अकेले चेयरमैन का नहीं होता

गावस्कर ने चयन समिति के भीतर फैसले लेने की प्रक्रिया का अहम पहलू भी सामने रखा। उनके मुताबिक किसी खिलाड़ी को चुनने या बाहर रखने का निर्णय कई बार केवल मुख्य चयनकर्ता का नहीं होता। समिति के अन्य चयनकर्ता भी चर्चा और फैसले में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद जब किसी फैसले को लेकर सवाल उठते हैं, तो मीडिया के सामने जवाब देने की जिम्मेदारी मुख्य चयनकर्ता पर ही आती है। बाकी चयनकर्ताओं की भूमिका पर्दे के पीछे रह सकती है, जबकि सार्वजनिक आलोचना का सामना चेयरमैन को करना पड़ता है।

अगरकर के कार्यकाल में कई बड़ी उपलब्धियां

अजीत अगरकर 2023 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता बने थे। उनके कार्यकाल में भारतीय टीम वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल तक पहुंची। इसके अलावा भारत ने टी20 विश्व कप 2024, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और टी20 विश्व कप 2026 जैसे बड़े टूर्नामेंट में खिताब जीते। अब नए मुख्य चयनकर्ता के सामने टीम में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, खिलाड़ियों के चयन और वरिष्ठ खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर कई अहम फैसले होंगे। नए चयनकर्ता की जिम्मेदारी ऐसे समय शुरू होगी, जब भारतीय टीम का कार्यक्रम बेहद व्यस्त है। टीम को न्यूजीलैंड दौरे पर पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय, तीन एकदिवसीय और दो टेस्ट मैच खेलने हैं। इसके साथ ही 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए टीम संयोजन और खिलाड़ियों के चयन को लेकर भी कई महत्वपूर्ण फैसले लेने होंगे।

15 हजार रन पूरे, लेकिन रिकॉर्ड पर नजर नहीं, विराट का बड़ा ऐलान

बल्लेबाजी में एक-दो गियर और बाकी मैदान पर अब भी होना है बहुत कुछ

तिरुवनंतपुरम, एजेंसी

विराट कोहली ने एक बार फिर अपने बल्ले से वनडे क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ी। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में 88 गेंदों पर नाबाद 139 रन की तूफानी पारी खेलकर कोहली ने भारत को 296 रन का लक्ष्य महज 41.4 ओवर में हासिल करा दिया। इस पारी के दौरान उन्होंने वनडे क्रिकेट में 15 हजार रन पूरे किए और सचिन तेंदुलकर के साथ इस खास क्लब में शामिल हो गए। हालांकि, इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद भी कोहली का कहना है कि व्यक्तिगत रिकॉर्ड कभी उनके लक्ष्य का हिस्सा नहीं रहे। उनका पूरा ध्यान परिस्थितियों को समझने और टीम के लिए अपना काम करने पर रहा है।

वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले में कोहली ने 10 चौकों और 9 छक्कों की मदद से 139 रन बनाए। उनकी पारी ने न केवल भारत को आसान जीत दिलाई, बल्कि वनडे क्रिकेट में उनके 15 हजार रन भी पूरे कराए। मैच के बाद कोहली ने कहा कि उनका ध्यान कभी भी मील के पत्थरों पर नहीं रहा। वह सिर्फ परिस्थिति के मुताबिक बल्लेबाजी करने और टीम के लिए योगदान देने पर ध्यान देते हैं। उनके मुताबिक व्यक्तिगत उपलब्धियां इसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

कोहली ने अपने लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर को लेकर खुद को भाग्यशाली बताया। उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय तक भारत के लिए खेलने का मौका मिलना उनके लिए बड़ी बात है। वह इसके लिए ईश्वर के आभारी हैं। कोहली के मुताबिक खिलाड़ी को हमेशा सिर झुकाकर मेहनत करते रहना चाहिए और उस सफर के लिए आभार जताना चाहिए, जिसने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया।

बल्लेबाजी में नया अंदाज तलाश रहे कोहली

कोहली ने अपने मौजूदा खेल को लेकर भी खुलकर बात की। उन्होंने माना कि करियर के इस पड़ाव पर बल्लेबाजी में एक-दो गियर ऊपर जाना उनके लिए चुनौती है। हालांकि, इसी चुनौती को वह रोमांचक भी मानते हैं। उनका कहना है कि अपने खेल का नया रूप तलाशना उन्हें उत्साहित करता है और इसका फायदा भारत के साथ-साथ उनकी आईपीएल टीम को भी मिल सकता है। कोहली ने कहा कि खुले दिमाग से खेलना उनके लिए काफी मददगार रहा है। अब वह परिस्थितियों के मुताबिक ज्यादा आक्रामक क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ लापरवाही से बचना भी उतना ही जरूरी है। पूर्व भारतीय कप्तान ने अपनी फिटनेस को मौजूदा बल्लेबाजी शैली का अहम हिस्सा बताया। उनका मानना है कि खुले दिमाग से खेलने के लिए शरीर का फिट रहना जरूरी है। जब शरीर पूरी तरह फिट होता है तो खिलाड़ी मैदान पर अपने खेल को बेहतर तरीके से महसूस कर सकता है और शॉट्स को उसी हिसाब से अंजाम दे सकता है।

हर मैच में खुद को देंगे चुनौती

अब जब कोहली भारतीय टीम के लिए वनडे प्रारूप में खेल रहे हैं, तो उनका लक्ष्य भी स्पष्ट है। 2027 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए वह आने वाले मुकाबलों में खुद को लगातार चुनौती देना चाहते हैं। वह अपनी फिटनेस के साथ-साथ मैदान पर अपनी ऊर्जा को भी बरकरार रखना चाहते हैं। कोहली का जोर मैच के आखिरी 15 ओवरों में भी पूरी ताकत से दौड़ने, इनर रिंग में प्रभावी क्षेत्ररक्षण करने और टीम के लिए हर संभव योगदान देने पर है।

यूएफा नेशंस लीग फुटबॉल

स्पेन ने इंग्लैंड को 3-2 से हराया, क्रोएशिया-स्विट्जरलैंड और फिनलैंड-लक्जमबर्ग भी जीते

लंदन। वेम्बली स्टेडियम में यूएफा नेशंस लीग के मुकाबले में विश्व चैंपियन स्पेन ने इंग्लैंड पर धमाकेदार जीत दर्ज की। स्पेन ने इंग्लैंड को 3-2 से हराया। स्पेन ने मैच के दूसरे मिनट में ही इंग्लैंड पर बढ़त बना ली। लामिन यमाल ने दूसरे मिनट में मार्क गुएही की गलती का फायदा उठाकर गोल किया। इंग्लैंड ने 36वें मिनट में एंथनी गॉर्डन के बराबरी के गोल से जवाब दिया, जो जूड बेलिंगहम के अच्छे काउंटर-अटैक का नतीजा था। फिर केन ने 40वें मिनट में निको ओ रेली के क्रॉस पर हेडर मारकर इंग्लैंड को हाफ-टाइम तक 2-1 की बढ़त दिला दी।

दूसरे हाफ की शुरुआत में रॉड्री के बेलिंगहम पर फाउल करने के बाद केन को पेनल्टी मिली, लेकिन उनका शॉट क्रॉसबार से टकरा गया, जिससे इंग्लैंड की बढ़त बढ़ाने का एक अहम मौका चूक गया। स्पेन ने 60वें मिनट में इंग्लैंड की गलती का फायदा उठाया, जब ओरेली की गलती के बाद सब्स्टीट्यूट एलेक्स बेना ने बॉक्स के किनारे से गोल किया। विजयी गोल 74वें मिनट में आया, जब मिकेल ओयारजाबल ने बेना के पास को गोल में बदला। वहीं, प्राग में खेले गए एक अन्य रोमांचक मुकाबले में क्रोएशिया ने चेकिया को 2-1 से हराया। मैच के दूसरे हाफ में लुका मोड्रिक ने पहला गोल किया। यह बढ़त ज्यादा देर तक नहीं रही और एडम करावेक ने गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया। इसके बाद मार्को पासालिक ने हेडर से गोल करते हुए क्रोएशिया को 2-1 से जीत दिला दी।

मनोरंजन | बॉलीवुड का कोना

शहजाद ने स्वरा भास्कर की उड़ाई खिल्ली सलमान के पुराने वीडियो का किया जिक्र

बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने फिल्मों के बाद अब रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' में अपनी मौजूदगी से सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं। शो में कदम रखते ही स्वरा अपने बेबाक अंदाज और खुलकर अपनी बात रखने के लिए चर्चा में हैं। वहीं, शो में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के साथ उनकी नोकझोंक भी दर्शकों का ध्यान खींच रही है। दोनों के बीच पहले दिन से ही तीखी बहस देखने को मिल रही है।

अब शो के एक एपिसोड में शहजाद पूनावाला स्वरा भास्कर पर तंज कसते नजर आए। उन्होंने साल 2019 में अभिनेत्री अर्पिता खान के गणपति विसर्जन के दौरान स्वरा के डांस का जिक्र किया। शहजाद ने इस पुराने वाकये को लेकर स्वरा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह दूसरे के गणपति विसर्जन में जाकर 'माइलेज और फुटेज' लेने के लिए डांस कर रही थीं। शहजाद ने इशारों-इशारों में सलमान खान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहां सलमान खान ने स्वरा को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था और अब शो में वह भी उसी अंदाज में उन्हें नजरअंदाज करने के मूड में हैं।

शहजाद ने स्वरा के बारे में बात करते हुए कहा, -एक बार माइलेज और फुटेज खाने के लिए किसी और के गणपति विसर्जन में जाकर ऐसे डांस कर रही थी और हमारे भाई ने इग्नोर कर दिया... हम भी वैसे ही इग्नोर मोड में हैं।- शहजाद का यह बयान शो में मौजूद प्रतिभागियों के बीच चर्चा का विषय बन गया। शहजाद के सोशल मीडिया हैंडल से इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ा वीडियो भी साझा किया गया है। वीडियो में शो के अंदर शहजाद को स्वरा पर तंज कसते हुए देखा जा सकता है।

पुराने वीडियो में साथ नजर आए थे सलमान और स्वरा

पुराने वीडियो में सलमान खान गणपति विसर्जन के दौरान पूरे जोश के साथ डांस करते नजर आते हैं। वहीं, उनके पास खड़ी स्वरा भास्कर भी डांस करती दिखाई देती हैं। शहजाद ने इसी पुराने वीडियो को आधार बनाकर शो में स्वरा पर निशाना साधा। उनका कहना था कि सलमान ने उस दौरान स्वरा की ओर ध्यान नहीं दिया था। स्वरा भास्कर और शहजाद पूनावाला के बीच सार्वजनिक मंचों पर पहले भी मतभेद और तीखी बयानबाजी देखने को मिल चुकी है। अब दोनों का एक ही रियलिटी शो में आमना-सामना हो रहा है। ऐसे में आने वाले एपिसोड में दोनों के बीच बहस और जुबानी टकराव और बढ़ता है या नहीं, यह शो के दर्शकों के लिए दिलचस्प होगा।

नई पीढ़ी की बदलती सोच पर बोले अभिषेक बनर्जी- अकेले रहना पसंद, शादी जरूरी नहीं

मुंबई। 'स्त्री', 'पाताल लोक' और 'मिर्जापुर' जैसे चर्चित प्रोजेक्ट्स में अपने अभिनय से पहचान बनाने वाले अभिनेता अभिषेक बनर्जी अपनी बेबाक राय के लिए भी जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने आधुनिक रिश्तों और नई पीढ़ी की बदलती सोच पर खुलकर बात की। उनका कहना है कि आज के युवा अकेले रहने में सहज हैं और उन्हें अपनी कंपनी का आनंद लेने में किसी तरह की परेशानी नहीं होती। युवा अब खुद से प्यार करने और अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। हाल ही में रिलीज हुई एंथोलॉजी 'लस्ट स्टोरीज 3' के प्रचार के दौरान आईएएनएस से बातचीत में अभिषेक बनर्जी ने कहा कि आज की पीढ़ी पहले के मुकाबले अकेले रहने को लेकर ज्यादा सहज है। युवा अपने साथ समय बिताने, खेल खेलने और अपनी पसंद की चीजें करने में खुश रहते हैं। अभिषेक के मुताबिक, खुद के साथ खुश रहना आज की पीढ़ी की बड़ी खूबी है। उनका मानना है कि हर व्यक्ति के लिए शादी करना या किसी रिश्ते में रहना ही जिंदगी का एकमात्र रास्ता नहीं है। लोग अब अपनी जरूरत, पसंद और परिस्थितियों के हिसाब से जिंदगी जीने के अलग-अलग तरीके चुन रहे हैं।

अभिषेक बनर्जी ने शादी और बच्चे करने की पारंपरिक सोच पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि समाज में एक तय ढांचा बना दिया गया है कि हर व्यक्ति को किसी से मिलना चाहिए, शादी करनी चाहिए, बच्चे करने चाहिए, उन्हें स्कूल भेजना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए और फिर बच्चों की शादी करनी चाहिए। अभिनेता ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि यह व्यवस्था पूरी तरह से विकास का हिस्सा है। उनके अनुसार, यह औद्योगिक क्रांति के दौर से विकसित हुई सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा ज्यादा है।

वित्तीय वर्ष 2027 में भारत के सोने का आयात घटने की संभावना

मेट्रो बाजार

मुंबई। सोने की कीमतों में तेज बढ़ोतरी, आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% किए जाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सोना खरीदने से बचने की सलाह का असर घरेलू मांग पर पड़ा है। इसके अलावा, दुनियाभर में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से महंगाई बढ़ने की चिंता ने भी सोने की मांग को कमजोर किया है। इसी को देखते हुए कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने वित्त वर्ष 2027 में भारत के सोने के आयात के अनुमान में 88 अरब डॉलर की कमी आने की संभावना जताई है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मई में सोने के मासिक आयात में गिरावट भी दर्ज की गई। हालांकि, कोटक का मानना है कि आने वाले त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने से सोने के आयात में कुछ सुधार हो सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2027 के अंत में 88 अरब अमेरिकी डॉलर के सोने के आयात का अनुमान फर्म ने लगाया है। हालांकि आगामी त्योहारी सीजन में मांग में तेजी की संभावना है। क्योंकि आगामी त्योहारी सीजन में मांग में तेजी आने की संभावना के साथ वित्त वर्ष 2027 से पहले महीने के रुझानों में सोने की गिरावट का जोखिम दिखाई दे रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2027 के पहले पांच महीनों में सोने का आयात 17.5 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले साल की समान अवधिक में 16.9 अरब अमेरिकी डॉलर का था। रिपोर्ट कहती है, वित्त वर्ष 2026 में कुल आयात 72 अरब अमेरिकी डॉलर का था। रिपोर्ट का दावा है, हाल में सरकार द्वारा सोने के आयात शुल्क में छह प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किए जाने की वजह से घरेलू बाजार में सोने की खरीदारी में कमी आई है।

टैक्स ऑडिट की डेडलाइन 30 सितंबर

बढ़ाने की मांग के बीच करदाताओं की बढ़ी चिंता; समय रहते निपटा लें जरूरी काम

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2025-26 यानी आकलन वर्ष 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 नजदीक आ गई है। टैक्स पेशेवरों और विभिन्न उद्योग संगठनों की ओर से समयसीमा बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से तारीख बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में करदाताओं को मौजूदा समयसीमा को ही ध्यान में रखकर अपनी तैयारी पूरी करने की सलाह दी जा रही है। आयकर अधिनियम की धारा 44एबी के तहत आने वाले करदाताओं को 30 सितंबर तक टैक्स ऑडिट पूरा कराकर ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त करनी होती है। पेशेवर संगठनों का कहना है कि इस बार आंकड़ों के मिलान, खुलासों और अनुपालन से जुड़े काम में अतिरिक्त समय लग रहा है। इसी वजह से कई संगठनों ने सरकार से समयसीमा आगे बढ़ाने की मांग की है।

करदाताओं को तुरंत करने होंगे ये 5 काम

दस्तावेज तैयार रखें: कारोबार से जुड़े लेखा-जोखा, बिक्री-खरीद रिकॉर्ड, बैंक विवरण, बिल, चालान और अन्य जरूरी दस्तावेज व्यवस्थित कर लें। रिकॉर्ड में कमी या विसंगति से ऑडिट में देरी हो सकती है।

आंकड़ों का मिलान करें: जीएसटी कारोबार, कर विवरण और वित्तीय आंकड़ों का पुस्तकों से मिलान करें। साथ ही फॉर्म 26एएस, एआईएस और टीआईएस में उपलब्ध जानकारी भी जांच लें।

महत्वपूर्ण लेनदेन की जांच: ऋण, स्थायी परिसंपत्तियों, संबंधित पक्षों, वैधानिक देनदारियों और बड़े खर्चों की विशेष जांच जरूरी है। इनके कर संबंधी उपचार को लेकर ऑडिटर से चर्चा कर लें।

4. ऑडिट रिपोर्ट और आईटीआर मिलाएं: टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और आयकर रिटर्न में कारोबार, खर्च, कटौती, कर संबंधी खुलासे और घाटे से जुड़े आंकड़े समान होने चाहिए। अंतर रहने पर आगे परेशानी हो सकती है।

15000 यात्री भारी बारिश से चारधाम में फंसे

केदारनाथ से 1200 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू

भारी बारिश ने पहाड़ों के सफर और ट्रैकिंग पर ब्रेक लगा दिया है। उत्तराखंड में 15 हजार से ज्यादा तीर्थयात्रियों को अलग-अलग जगहों पर रोका गया। कालिंदी ट्रैक समेत तमाम स्थानों पर फंसे पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। केदारनाथ से 1200 यात्री रेस्क्यू किए गए हैं। छह हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं और संभावित रेस्क्यू प्वाइंट के आसपास हेलीपैड चिन्हित करते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं।

LOC हटाने, पुंछ-मेंढर के रास्ते खोलने की मांग

PoK में फिर संग्राम, सड़क पर उतरे 25000 लोग

नई दिल्ली। एजेंसी

पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर यानी PoK में एक बार फिर बड़ा प्रदर्शन हुआ है। मंधोल गांव में आयोजित इस रैली में 25 हजार से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा किया गया है। यह गांव LoC से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर है. पूरे दिन चले इस प्रदर्शन का नेतृत्व जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JKJAAC के नेता सरदार अमान खान ने किया. अमान खान पिछले कुछ महीनों से चल रहे इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे हैं।

रैली में पाकिस्तान के नियंत्रण के खिलाफ आवाज उठाई गई। प्रदर्शनकारियों ने रूष्ट को खत्म करने और इलाके को भारत से जोड़ने वाले पुराने रास्तों को फिर से खोलने की मांग का समर्थन किया। खास तौर पर पुंछ और मेंढर के रास्ते दोबारा खोलने की बात कही गई। रैली के दौरान सरदार अमान खान ने भीड़ से तीन सवाल पूछे और हर सवाल पर लोगों से समर्थन मांगा. रिपोर्ट के मुताबिक, भीड़ ने तीनों सवालों का जवाब 'हां' में दिया। मंधोल में हुई यह रैली PoK में चल रहे व्यापक आंदोलन का हिस्सा बताई गई है। इससे पहले रावलाकोट और PoK के दूसरे इलाकों में भी बड़ी रैलियां हो चुकी हैं।

सीजफायर लाइन खत्म करने की मांग

सरदार अमान खान ने सबसे पहले लोगों से पूछा कि क्या सीजफायर लाइन को खत्म किया जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने सवाल किया कि क्या LoC पर लगी फेंसिंग को हटाने की मांग को लेकर वहीं धरना दिया जाना चाहिए. तीसरा सवाल पुंछ और मेंढर के रास्तों को दोबारा खोलने को लेकर था। भीड़ ने तीनों मांगों पर समर्थन जताया। अमान खान ने कहा कि जल्द ही LoC की फेंसिंग के पास धरना दिया जाएगा। इस धरने के जरिए फेंसिंग हटाने की मांग की जाएगी, ताकि स्थानीय लोग भारत के साथ पुराने संपर्क को फिर से जोड़ सकें। मंधोल में हुई रैली में भी पुराने रास्तों को दोबारा खोलने की मांग प्रमुख तौर पर उठाई गई।

पाकिस्तान आर्मी पर भी लगाए आरोप

रैली के दौरान अमान खान ने पाकिस्तान आर्मी पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि जब रूष्ट के आसपास फायरिंग शुरू हुई तो सेना के जवान अपनी बैरकों में छिप गए. उन्होंने कहा कि इसी दौरान स्थानीय लोगों ने उन सैनिकों को शरण दी। अमान खान ने आरोप लगाया कि जिन स्थानीय लोगों ने मुश्किल वक्त में सेना के जवानों को बचाया, उन्हीं लोगों को पाकिस्तान आर्मी ने पिछले कई महीनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान निशाना बनाया। उनके इस बयान का मकसद पाकिस्तान के नियंत्रण और सेना की भूमिका के खिलाफ चल रहे आंदोलन को और तेज करना था। मंधोल में हुई यह रैली PoK में चल रहे व्यापक आंदोलन का हिस्सा बताई गई है। इससे पहले रावलाकोट और PoK के दूसरे इलाकों में भी बड़ी रैलियां हो चुकी हैं। इन प्रदर्शनों में स्थानीय मुद्दों के साथ पाकिस्तान के नियंत्रण को लेकर भी आवाज उठाई गई है। सरदार अमान खान और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के दूसरे नेता 'आजाद कश्मीर' नाम को भी खारिज करते रहे हैं।

न्यूज विंडो

बारिश से कच्चे मकान की दीवार ढही, परिवार के 8 लोग गंभीर

कानपुर, एजेंसी । सचेंडी के कैधा नयापुरवा गांव में लगातार हो रही बारिश के चलते सोमवार भोर पहर एक कच्चे मकान की दीवार भरभराकर गिर गई। हादसे में दीवार से ऊपर पड़े छप्पर के नीचे सो रहे परिवार के आठ लोग दीवार के मलबे में दब गए। आनन फानन में ग्रामीणों ने मलवे को हटाकर सभी को सीएचसी भेजा। जहां डॉक्टरों ने चार लोगों की हालत गंभीर बताकर एलएलआर अस्पताल रेफर कर दिया है। कैधा नयापुरवा गांव निवासी मुन्ना सिंह अपनी पत्नी रमाकांती,बेटे दीपक ,शुभम ,रौनक,बेटी अंजली,रिंकी और पिंकी के साथ रहते हैं।उनका मकान कच्चा है,रविवार रात वह कोठरी से सटे छप्पर के नीचे परिवार के साथ सोए हुए थे।सोमवार भोर पहर करीब तीन बजे कोठरी की दीवार भरभराकर ढह गई।जिसके मलबे में वह परिवार समेत दब गए।

सोलापुर के किसानों ने लगाए पोस्टर 'हमारा पूरा गांव बिकाऊ है'

सोलापुर, एजेंसी। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के तुलशी गांव में एक पोस्टर लगा है जिस पर लिखा है, 'गांव बिकाऊ है '। ये शब्द उन निवासियों के गुस्से, तंज और गहरी बेचैनी को जाहिर करते हैं जो दशकों से सिंचाई के पानी का इंतजार कर रहे हैं। सरपंच शरद मोरे कहते हैं, 'जो कोई भी हमारा गांव खरीदना चाहता है, वह आगे आ सकता है। बाहरी लोगों के लिए यह पोस्टर मजेदार हो सकता है लेकिन यह दिखाता है कि सरकार पिछले 25 सालों से हमें कैसे बेवकूफ बना रही है। तुलशी गांव सीना-माढ़ा लिफ्ट सिंचाई योजना से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है। यह योजना साल 2000 में शुरू हुई थी लेकिन तुलशी को इसका कोई फायदा नहीं मिला। आस-पास के दूसरे गांव ज्यादा पानी वाली नकदी फसलें उगाते हैं, जबकि तुलशी गांव अनिश्चित बारिश का इंतजार करता रहता है। जिले के रिकॉर्ड के मुताबिक, माढ़ा के कई गांवों में पिछले 45 दिनों से बारिश नहीं हुई है।

होर्मुज में 'कर्फ्यू' के बीच नेतन्याहू पहुंचे यूएई, अमेरिका की सीक्रेट तैयारी

नई दिल्ली। एजेंसी

आजकल सबकी जुबान पर एक ही बात है- पश्चिम एशिया में जारी अमेरिका-इजरायल-ईरान युद्ध में आगे क्या होगा? दुनिया के तमाम देश इस क्षेत्र में शांति की बहाली के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं निकल सका है। इसके उलट अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग के और खतरनाक होने की आशंका गहरा गई है। एक के बाद एक हुई 3 घटनाओं से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पहली, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बेहद गोपनीय तरीके से अबू धाबी की यात्रा की है। दूसरी, इस क्षेत्र में अमेरिकी हेवी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का जमावड़ा हो रहा है। तीसरी, होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही बिल्कुल ही बंद हो चुका है। वेस्ट एशिया में जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, उससे इस बात का अंदेशा गहरा गया है कि अमेरिका के नेतृत्व में ईरान के खिलाफ फाइनल अटैक किया जा सकता है। दूसरी तरफ, ईरान का भी कहना है कि वह अमेरिका और इजरायल के खिलाफ अंतिम युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में पश्चिम एशिया में आने वाले दिनों में टकराव बढ़ने की आशंका गहरा गई है।

जानकारी के अनुसार, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी की गुप्त यात्रा की। इस दौरान उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। दो सूत्रों ने इजरायली समाचार चैनल एन12 से बातचीत में इस यात्रा की पुष्टि की है। नेतन्याहू कथित तौर पर निजी विमान से अबू धाबी पहुंचे और पूरे दिन अमीरात में रहने के बाद इजरायल लौटे। यात्रा की पहले से कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई थी। नेतन्याहू के कार्यालय ने मुलाकात की पुष्टि या उसके एजेंडे से जुड़े सवालों पर कोई विवरण देने से इनकार किया है।

वेस्ट एशिया में लगा अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट का रेला

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच बड़ी संख्या में अमेरिकी सी-130 एच मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की क्षेत्र की ओर आवाजाही लगातार दूसरे दिन देखा गया. यह गतिविधि ऐसे समय में हुई है, जब एक दिन पहले भी बड़ी संख्या में अमेरिकी सैन्य विमानों के वेस?ट एशिया की ओर बढ़ने की सूचना सामने आई थी. सी-130 एच एक सामरिक परिवहन विमान है, जिसका इस्तेमाल सैनिकों, गोला-बारूद, हथियारों, वाहनों और अन्य सैन्य उपकरणों को युद्ध क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है. यह विमान करीब 42,000 पाउंड तक सामान या लगभग 90 सैनिकों को ले जा सकता है और छोटी तथा कठिन हवाई पट्टियों से भी संचालन करने में सक्षम है. अमेरिका की यह बढ़ी सैन्य गतिविधि ऐसे समय में हो रही है, जब होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास तनाव काफी बढ़ गया. ईरान ने अपनी सैन्य तैयारियों को हाई अलर्ट पर रखा है, जबकि अमेरिका क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है. हालांकि, विमानों की इस आवाजाही के उद्देश्य को लेकर तत्काल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

ठाणे में तेज रफ्तार दो वैन भिड़ीं, पिता-बेटे समेत तीन की मौत

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र के ठाणे में मालशेज घाट के पास एक हाइवे पर तेज रफ्तार दो वैन की टक्कर हो गई। हादसे में पिता-बेटे और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने सोमवार को घटना की जानकारी दी।

हादसा रविवार सुबह मुरबाड तालुका में नेशनल हाईवे नंबर 61 पर हुआ। पुलिस अधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि खेडले-तालवाले गांव के तीन लोगों को ले जा रही एक पिकअप वैन की टक्कर कल्याण की ओर जा रही एक पोल्ट्री वैन से हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

भारतीय दवा कंपनियों के लिए अमेरिका का फैसला

चुनिंदा दवाओं पर नहीं लगेगा टैरिफ, फार्मा कंपनियों को राहत

वॉशिंगटन। एजेंसी

अमेरिका ने भारत की चुनिंदा दवाओं और दवा बनाने वाली सामग्री को जीरो टैरिफ वाली सूची में शामिल किया है। इसमें ऑरफन ड्रग्स, फर्टिलिटी दवाएं, सेल और जीन थेरेपी जैसी दवाएं शामिल हैं। इस फैसले से भारतीय फार्मा कंपनियों राहत मिल सकती है। भारत से अमेरिका भेजी जाने वाली कुछ खास दवाओं और दवा बनाने वाले कच्चे माल पर अब जीरो अमेरिकी टैरिफ लागू होगा।

इससे अमेरिका को दवाएं सप्लाई करने वाले भारत के फार्मा सेक्टर को बड़ी राहत मिल सकती है। यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट ने यह लिस्ट तब जारी की है जब वॉशिंगटन 29 सितंबर से कुछ पेटेंटेड फार्मास्युटिकल इंपोर्ट और उनसे जुड़ी सामग्री पर 100% टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। यह छूट भारत से भेजे जाने वाले हर फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट पर लागू नहीं होती है। यह अप्रैल में जारी राष्ट्रपति के आदेश में बताई गई खास दवाओं और सामग्री पर लागू होती है। योग्य प्रोडक्ट्स में ऑरफन ड्रग्स, न्यूक्लियर दवाएं, प्लाज्मा से बनी थेरेपी, फर्टिलिटी दवाएं, सेल थेरेपी, जीन थेरेपी और एंटीबॉडी-ड्रग कॉन्जुगेट्स शामिल हैं।

बिहार में नाबालिग से छेड़खानी का सीसीटीवी आया सामने

मुजफ्फरपुर,एजेंसी

मुजफ्फरपुर जिले में एक नाबालिग लड़की से छेड़खानी, मारपीट और जबरन घसीटकर ले जाने के चार दिन पुराने मामले का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। इस फुटेज को बिहार के प्रमुख विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर बिहार में हो रही घटनाओं और कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा है। हालांकि, 23 सितंबर को हुई इस घटना के बाद से ही नगर थाना पुलिस आरोपी ललित कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज चुकी है। अब चार दिन बाद राजद ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बिहार सरकार और राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। दरअसल, पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा मोहल्ले का है। यहां 23 सितंबर को मोहल्ले की एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी और मारपीट की घटना हुई थी। आरोप है कि युवक ने नाबालिग लड़की को सड़क के पास ही पहले घर से खींचकर अपने साथ ले जाने की कोशिश की। जब लड़की ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। घटना के बाद परिजनों ने नाबालिग लड़की का सदर अस्पताल में इलाज कराया।

मेट्रो एंकर | यूके-यूएस की खुफिया एजेंसिया को पता भी नहीं लगा, ईरान की साजिश होने की शंका

महिला की सतर्कता ने बचा लिया अमेरिकी एयरबेस

नई दिल्ली। एजेंसी

ब्रिटेन के एक शांत गांव में रविवार सुबह अचानक ऐसा मंजर दिखा, जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन हो। यहां बंदूक लिए पुलिस वाले, बम निरोधक दस्ता तैनात थे। तीन संदिग्ध वैन को घेरा जा चुका था और घरों से लोगों को जल्दी-जल्दी निकाला जा रहा था। अमेरिकी वायुसेना के बॉम्बर जिस बेस में रहते हैं, उस आरएएफ फेयरफोर्ड (फायरफोर्ड) के पास पांच संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई। इस गिरफ्तारी ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। करीब 85 घर खाली कराए गए, तीन वैन की जांच के लिए सेना का बम निरोधक दल पहुंचा और मामला अब आतंकवाद रोधी पुलिस के हाथ में है। माना जा रहा है कि एयरबेस को दहलाने की साजिश थी।

ऐसे पकड़ाए संदिग्ध

इस पूरे मामले में एक स्थानीय महिला की सतर्कता ने काम किया। तड़के उसने गांव में तीन संदिग्ध वैन देखीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे इन वाहनों और उनमें मौजूद लोगों की गतिविधियां सामान्य नहीं लगीं। उसने पुलिस को तुरंत फोन किया। पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में लिया। शुरुआती कार्रवाई रात करीब 12:45 बजे शुरू हुई। तीन संदिग्ध वाहन आरएएफ फायरफोर्ड की दिशा में जा रहे थे. पांचों को आतंकवादी हमले की तैयारी के संदेह में भी गिरफ्तार किया गया।

तीन वैन, रोबोट और 400 मीटर का घेरा

मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सेना के एक्सपर्ट बम निरोधक टीम को बुलाया गया। तीनों वैन की जांच की जा रही है और उनके आसपास करीब 400 मीटर का सुरक्षा घेरा बनाया गया। हवाई तस्वीरों में बम निरोधक रोबोट को वैन के आसपास जांच करते देखा गया। पुलिस ने एहतियात के तौर पर व्हेलफोर्ड के करीब 85 घरों को खाली कराया और लोगों को पास के मनोरंजन केंद्र में पहुंचाया। ब्रिटिश आतंकवाद रोधी पुलिस ने कहा है कि पांचों लोग हिरासत में हैं और जांच अभी शुरुआती दौर में है।

'हॉलीवुड फिल्म जैसा लग रहा था'

व्हेलफोर्ड के लोगों के लिए यह सुबह बिल्कुल अलग नजारा था। एक एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक स्थानीय निवासी ने इसे शांत गांव में हॉलीवुड फिल्म जैसा नजारा बताया। कई लोगों को घर से जरूरी सामान लेकर तुरंत बाहर निकलने को कहा गया। एक व्यक्ति के मुताबिक सुबह करीब 7 बजे पुलिस ने दरवाजा खटखटाकर घर खाली करने को कहा। सड़कें बंद थीं, पुलिस बंदूकों के साथ तैनात थी और बड़ी संख्या में आपातकालीन वाहन इलाके में खड़े थे। इमरजेंसी सर्विसेस की करीब 30 गाड़ियां मौके पर थीं, जिनमें पुलिस की गाड़ियां, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां शामिल थीं। जिस जगह यह पूरा घटनाक्रम हुआ, वह कोई सामान्य सैन्य अड्डा नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इसमें ईरान का हाथ है? लेकिन फिलहाल इसका जवाब नहीं मिला है। ईरान की ओर से पहले ब्रिटेन को अमेरिकी के लिए अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी भी सामने आई थी। ऐसे में जांच में ईरान कनेक्शन की संभावना पर भी नजर होने की खबरें हैं, लेकिन अभी किसी सरकारी एजेंसी ने गिरफ्तार लोगों को ईरान से जोड़ने की पुष्टि नहीं की है।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक **राजेश सिरोठिया** द्वारा पी जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,करोंद-भानपुर बाइपास विलेज रासलाखेड़ी भोपाल से मुद्रित तथा ए-182 मनीषा मार्केट शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। **संपादक राजेश सिरोठिया**
स्थानीय संपादक अनिल शर्मा* आर एन आई पंजीयन क्रमांक एमपी एचआईएन/2016/68849 (*पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार) **फोन :** 0755-7963564, 4917524